

4th Year
Anniversary

यूटर्न टाइम्स

The Good, Bad and Ugly of India

FOLLOW US ON @UTURNTIMENEWS

गुस्ताखी माफ

मौसम ने भी आजकल, पकड़ रखा पाखंड।
गर्म बहुत था फरवरी, हुई मार्च में ठंड।
हुई मार्च में ठंड, धिरे हैं बादल ऐसे।
लगी हुई है झड़ी, झड़ी सावन की जैसे।
कह साहिल कविराय, अजब मौसम का फंडा।
गर्म करे अप्रैल, मई हो फिर से ठंडा।

- डॉ. राजेन्द्र साहिल

VOL: 11 | ISSUE 67 | SATURDAY 21-03-2026 | RS-03 | PAGE-12 | PUBLISHED BY: LUDHIANA | HINDI DAILY NEWSPAPER

Visit at : www.uturntime.com

कारपोरेशन में रिश्वत लेकर दर्जा चार कर्मियों की भर्ती करने के आरोप, मेयर के पति, सेनेटरी इंस्पेक्टर व नंबरदार खिलाफ सीएम और विजिलेंस को शिकायत

क्या सच में हुआ भ्रष्टाचार या रहा सिर्फ बदनाम करने को किया जा रहा राजनीतिक स्टंट ?

लुधियाना/यूटर्न/20 मार्च। लुधियाना नगर निगम में अक्सर ही मुलाजिमों की भर्तियां करने को लेकर मामले सामने आते रहते हैं। जहां कुछ महीने पहले एक दर्जा चार महिला कर्मियों द्वारा एक लीडर पर पैसे लेकर भर्ती करने के आरोप लगाए थे, वहीं अब एक और नया मामला सामने आया है। जिसमें दर्जा चार कर्मियों की भर्ती कराने को लेकर लाखों रुपए की रिश्वत का खेल होने के आरोप लगाए गए हैं। इस संबंधी अब्दुलपुर बस्ती के रहने वाले कमल द्वारा सीएम पंजाब भगवंत मान, विजिलेंस ब्यूरो पंजाब और लुधियाना को लिखित में शिकायत भेजी गई है। इस शिकायत में कमल नामक व्यक्ति द्वारा सीधे तौर पर चीफ सेनेटरी ऑफिसर (सीएसओ) गुरिंदर सिंह, नंबरदार राकेश कुमार व एक लीडर के दामाद पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं मेयर प्रिंसिपल इंद्रजीत कौर के पति रवि आनंद लक्की पर अधिकारियों द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को अंजाम तक पहुंचाने में सहायता करने के आरोप लगे हैं। हालांकि शिकायत करने वाला व्यक्ति खुलकर सामने नहीं आ रहा है। अब यह चर्चा छिड़ गई है कि इस मामले में सच में भ्रष्टाचार हुआ है या फिर बदनाम करने के लिए राजनीतिक स्टंट खेला जा रहा है। वहीं इस मामले की जांच नगर निगम कमिश्नर को सौंपी गई है। अब देखना होगा कि इस मामले की जांच के बाद क्या असलियत निकलकर सामने आती है।



पूर्व निगम कमिश्नर की जांच बीच में रुकवाई

वहीं शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब 200 सफाई कर्मियों की भर्ती हुई तो सीएसओ और नंबरदार द्वारा मेयर के पति रवि आनंद लक्की के साथ सेटिंग की और फिर तीनों ने मिलकर पूरे खेल को अंजाम दिया। वहीं इस खेल में एक नेता के दामाद पर भी आरोप लगे हैं। कमल ने यह भी आरोप लगाया कि यह मामला चर्चा में आने के बाद पूर्व निगम कमिश्नर द्वारा मामले की जांच शुरू की। कमिश्नर द्वारा सीएसओ गुरिंदर सिंह के खिलाफ ऑर्डर भी जारी कर दिए थे। लेकिन फिर राजनीतिक दबाव डालकर जांच को रुकवा दिया गया। यहां तक कि हफ्ते बाद ही गुरिंदर सिंह खिलाफ जारी ऑर्डर भी रद्द करवा दिए गए।

सीएसओ पर बेनामी जायदाद बनाने के आरोप

शिकायतकर्ता कमल ने अपनी शिकायत में यह भी आरोप लगाए हैं कि सीएसओ गुरिंदर सिंह का खन्ना में 500 गज का प्लॉट है। इसके अलावा उन्होंने अपनी पत्नी के नाम पर काफी बेनामी जायदाद खरीद रखी है। वहीं कमल का यह भी आरोप है कि सीएसओ रोजाना कभी लुधियाना और कभी फगवाड़ा जाता है। आखिर उनके पास इतना तेल का खर्च कहा से आता है। इसकी गहनता से जांच हो तो बड़े खुलासे होने की संभावना है।

मामले की जांच जारी, जल्द सच सामने आएगा

मेयर इंद्रजीत कौर अनुसार उपचुनाव के दौरान खे गई कर्मियों की पूरी वेरीफिकेशन हुई थी। वहीं शिकायत में एक साल पहले की बात की जा रही है, तब मेरे पास मेयरशिप भी नहीं थी। शिकायत भेजने वाले न तो अपना नंबर दिया और न पूरा पता बताया। यह सिर्फ बदनाम करने का प्रयास है। मामले की जांच चल रही है। शिकायतकर्ता को पक्ष रखने को बुलाया है। जल्द सच सामने आ जाएगा। अगर मामले में कोई दोषी पाया गया तो बनती कार्रवाई होगी, फिर चाहे मेरे परिवार का मेंबर क्यों न हो। अगर शिकायत झूठी निकली, तो शिकायतकर्ता से पता लगाया जाएगा कि उसने किसके कहने पर यह सब किया। किसी पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन प्रूफ करना मुश्किल। कुर्सी पर अच्छे काम करने वालों की टांगें बहुत लोग खिंचते हैं। वैसे भी भर्ती जोन-डी में हुई थी और यह आरोप जोन-सी में भर्ती के लगाए जा रहे हैं।

प्रति कर्मों 1.70 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप

वहीं शिकायतकर्ता कमल द्वारा अपनी शिकायत में कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उसका आरोप है कि करीब साल पहले निगम जोन-सी में दर्जा चार कर्मियों की भर्तियां की गई। आरोप है कि यह भर्तियां सीएसओ गुरिंदर सिंह और नंबरदार राकेश कुमार द्वारा की गईं। जिसमें प्रति कर्मों 1.70 लाख रुपए की रिश्वत ली गई। इस तरह करके 80 मुलाजिम भर्ती किए गए। कमल का आरोप है कि उसकी भी इसी तरह रिश्वत लेकर भर्ती हुई। अब वह सीएसओ गुरिंदर सिंह से अपने पैसे वापिस मांग रहा है तो वह टाल मटोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने कभी किसी को पैसे वापिस नहीं दिए, तुझे भी नहीं मिलेंगे।

सीएमओ और विजिलेंस से खुद जांच करने की मांग

वहीं शिकायतकर्ता कमल ने यह मांग की कि इस मामले की जांच लोकल लेवल पर सही तरीके से नहीं हो सकती। जिसके चलते उसने सीएम पंजाब और विजिलेंस विभाग को खुद अपने सत्र पर जांच करने की मांग की है। हालांकि सीएमओ ऑफिस की तरफ से मामले की जांच संबंधी लोकल बॉडी विभाग को पत्र भेजा। लोकल बॉडी विभाग द्वारा पांच फरवरी को मामले की जांच कर बनता एक्शन लेने के लिए निगम कमिश्नर नीरू कत्याल को पत्र भेजा है।

सच में हुआ भ्रष्टाचार या बदनाम करने का प्रयास ?

वहीं इस शिकायत के सामने आने के बाद शहर में चर्चा छिड़ गई है। चर्चा है कि क्या सच में भ्रष्टाचार हुआ है या सिर्फ बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। चर्चा यह भी है कि जल्द विधानसभा चुनावों का बिगुल बज सकता है। ऐसे में यह राजनीतिक स्टंट भी हो सकता है। लेकिन मामले का असली सच क्या है, ये तो जांच के बाद ही सामने आ सकेगा।



विरोधियों द्वारा बदनाम करने का प्रयास

वहीं मेयर प्रिंसिपल इंद्रजीत कौर के पति रवि आनंद ने कहा कि सीएसओ गुरिंदर सिंह से आज तक न तो उनका कभी संपर्क हुआ और न ही कभी मुलाकात हुई। जिस नंबरदार राकेश कुमार का नाम लिया जा रहा है, उन्हें पता नहीं है कौन है। उनका वॉर्ड जोन-बी के साथ अटैच है, जोन-सी से उनका कोई लिंक ही नहीं है, जबकि यह भर्तियां जोन-सी में होने की बात कही जा रही है। यह सिर्फ विरोधियों द्वारा बदनाम करने का प्रयास है। शिकायत करने वाला कौन है, कहा का है, किसी को कुछ नहीं पता। यह भ्रष्टाचार एक साल पहले का बताया जा रहा है। तब तो लुधियाना मेयर की नियुक्ति भी नहीं हुई थी। फिर हम इसमें कैसे शामिल हो सकते हैं।

जानबूझकर परेशान करने का प्रयास

सीएसओ गुरिंदर सिंह अनुसार यह शिकायत फेक है। किसी की ओर से जानबूझकर परेशान करने का प्रयास किया जा रहा है। मेरी पोस्टिंग लुधियाना में नहीं बल्कि फगवाड़ा में है। अब कुछ दिन के लिए मुझे जोन-सी का एडिशनल चार्ज मिला है।

चैत्र नवरात्रि
तीसरा दिन मों चंद्रघंटा
मक्तों की सभी मनोकामनाएँ पूर्ण करें।
श्री भगवत कथा
19 मार्च 2026 से 25 मार्च 2026 तक। सार्व 4:15 बजे से 7:15 बजे तक
श्री दुर्गा माता मंदिर, पन्थीक बगइचा पुल, लुधियाना में

कथा व्यास
श्री गुरुदेव गुरुदेव श्री गुरुदेव गुरुदेव श्री गुरुदेव
श्री गुरुदेव गुरुदेव श्री गुरुदेव गुरुदेव श्री गुरुदेव

श्री ए.एस. सुकन (ANSAL WEALTH ADVISORS) एवं एडवोकेट

बागबानी विभाग लुधियाना देशभर में अटवल, एआईएफ स्कीम में हासिल किया पहला स्थान



लुधियाना, यूटर्न, 20 मार्च। बागबानी विभाग, लुधियाना ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) स्कीम के तहत देशभर में पहला स्थान हासिल कर बड़ी उपलब्धि दर्ज की है। पंजाब के बागबानी मंत्री महिंदर भगत ने इस उपलब्धि पर जिले को बधाई देते हुए भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया। भारत सरकार की इस योजना को पंजाब में लागू करने के लिए बागबानी विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है, जिसके तहत पंजाब ने लगातार दूसरी बार देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि विभाग की कुशल कार्यप्रणाली और बेहतर समन्वय का परिणाम है। मगसीपा, चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिलों और बच्चों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बागबानी मंत्री महिंदर भगत मुख्य अतिथि और प्रमुख सचिव अरशदीप सिंह थिंद विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। जिला लुधियाना की ओर से अतिरिक्त उपायुक्त जशनप्रीत कौर, डिप्टी डायरेक्टर डॉ. दलवीर सिंह और अन्य अधिकारियों को सम्मानित किया गया। एआईएफ स्कीम के तहत जिले में 3650 परियोजनाएं स्वीकृत हुईं, जिनमें किसान, एग्री उद्यमी, एफपीओ, स्टार्टअप और सहकारी संस्थाएं शामिल हैं।

Celebrate your Birthday
or Anniversary with **UTURN TIME**
in association with

Hot Breads
0161-4603333, 5012222

**2 LUCKY WINNERS
WILL GET CAKE WORTH
OF ₹1200 EACH**

*WINNERS WILL BE DECIDED
THROUGH LUCKY DRAW

FOR MORE DETAILS, CALL: 99882-20063, 98 142-95372
janhetaishi@gmail.com, hetaishinews@gmail.com

All rights about Distribution & Offer will be
reserved by **U-TURN TIME MANAGEMENT** Only.

एटीआईयू ने पेट्रोल के बढ़े दामों को लेकर जताई चिंता

लुधियाना/यूटर्न/20 मार्च। एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन (एटीआईयू) के अध्यक्ष पंकज शर्मा ने एलडीओ, फर्नेस ऑयल और पेटकोक जैसे



पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में अचानक और लगातार हो रही वृद्धि पर गहरी चिंता व्यक्त की, जो पिछले 20 दिनों में लगभग 25% तक बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि इस तीव्र वृद्धि ने औद्योगिक कार्यों, विशेष रूप से फोर्जिंग क्षेत्र को बुरी तरह

प्रभावित किया है। एटीआईयू के कार्यकारी सदस्य, चामुंडा फोर्जिंग्स के कैप्टन राजेश मित्तल, टीसीजी फोर्जिंग्स के राहुल गुप्ता और एसएन ब्रदर्स के नीरज धामिजा ने बताया कि ईंधन की कीमतों में इस तरह की अप्रत्याशित और तीव्र वृद्धि के कारण फोर्जिंग उद्योगों को अपने उत्पादन चक्र की योजना बनाने में बेहद कठिनाई हो रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस स्थिति का ट्रेक्टर पुर्जों, कृषि उपकरणों, साइकिल पुर्जों और ऑटो घटकों की आपूर्ति श्रृंखला पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। भारतीय रेलवे के प्रमुख आपूर्तिकर्ता, चामुंडा कास्टिंग्स लिमिटेड के निदेशक राघव मित्तल ने बताया कि विभिन्न सरकारी विभागों को आपूर्ति भी बुरी तरह प्रभावित हो रही है। अचानक हुई वृद्धि के कारण, उन अनुबंधित दरों पर ऑर्डर पूरे करना अव्यवहारिक हो गया है। एटीआईयू के उपाध्यक्ष और डी डी स्टील कास्टिंग्स लिमिटेड के मालिक आयुष गुप्ता ने कहा कि पेटकोक की कीमतों में आई तीव्र वृद्धि ऊर्जा-गहन उद्योगों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन गई है। डायना स्टील प्रोडक्ट्स के राजेश सचदेव का मानना है कि इस वृद्धि का सिलाई मशीन, इंडक्शन मोल्ड और अन्य कास्टिंग से संबंधित उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

लालडू पुलिस ने 414 ग्राम अफीम समेत युवक को किया गिरफ्तार

लालडू, यूटर्न, 20 मार्च। स्थानीय पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 414 ग्राम अफीम के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान सालकिशन उर्फ भोलू निवासी राजस्थान के रूप में हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार टीम गश्त के दौरान संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर रही थी। इसी दौरान जब पुलिस अंबाला-चंडीगढ़ हाईवे पर झरमल नदी के पुल के पास पहुंची तो एक युवक पीठ पर बैग लटकाए जाता दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वह घबरा गया और तेज चलने लगा, जिससे उस पर शक हुआ। शक के आधार पर पुलिस ने युवक को रोककर उसके बैग की तलाशी ली, जिसमें से 414 ग्राम अफीम बरामद हुई।

टाटा स्टील प्लांट का उद्घाटन, हलवारा एयरपोर्ट से प्लाइट की ऑनलाइन बुकिंग अगले सप्ताह से : मंत्री अरोड़ा

लुधियाना, यूटर्न, 20 मार्च। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लुधियाना में टाटा स्टील के देश के दूसरे सबसे बड़े अत्याधुनिक प्लांट का उद्घाटन किया। करीब 3200 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह प्लांट पंजाब के औद्योगिक विकास में एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से राज्य में निवेश को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस प्लांट के शुरू होने से 2600 से 2700 युवाओं को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा, जबकि करीब 10 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने बताया कि यह प्लांट ग्रीन ऊर्जा आधारित इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस तकनीक पर कार्य करेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण के साथ उत्पादन को भी बढ़ावा मिलेगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार की उद्योग-समर्थक नीतियों के कारण पंजाब में एक बार फिर औद्योगिक माहौल मजबूत हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकारों की



गलत नीतियों के चलते कई उद्योग राज्य से बाहर चले गए थे, लेकिन

अब वे वापस लौट रहे हैं। इस मौके पर उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि हलवारा एयरपोर्ट से ऑनलाइन टिकट बुकिंग अगले सप्ताह से शुरू कर दी जाएगी। इससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और उद्योग एवं व्यापार को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने टाटा समूह की सराहना करते हुए कहा कि उनका निवेश पंजाब के भविष्य में विश्वास को दर्शाता है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योग जगत से जुड़े कई गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

शर्मिंदगी और परेशानी: एयर इंडिया ने यात्रियों से भरा ऐसा विमान भेजा जिसे कनाडा में घुसने का कोई अधिकार नहीं था, विमान ने यूटर्न लिया

चंडीगढ़/यूटर्न/20 मार्च। वैकूवर जा रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट कल हवा में लगभग आठ घंटे बिताने के बाद दिल्ली लौट आई, क्योंकि एयरलाइन ने गलती से एक ऐसा विमान भेज दिया था जिसके पास कनाडा में घुसने के लिए जरूरी मंजूरी नहीं थी। फ्लाइट एआई185 सुबह 11:34 बजे यात्रियों के साथ दिल्ली से रवाना हुई और शुरू में पूरब की ओर वाले रास्ते पर आगे बढ़ी। हालांकि, सफर के चार घंटे से ज्यादा बीत जाने के बाद, जब विमान कुनमिंग के पास चीनी हवाई क्षेत्र में घुसा, तो एयरलाइन को एहसास हुआ कि इस विमान को कनाडा में उड़ान भरने की इजाजत नहीं है। वापसी में इतना ज्यादा समय लगने की वजह से, विमान कुल 7 घंटे 54 मिनट तक उड़ा और वहीं उतरा जहाँ से उसने उड़ान भरी थी। यह विमान एक Boeing 777-200LR था, जबकि एयर इंडिया के पास फिलहाल कनाडा के लिए अपनी सेवाओं पर सिर्फ Boeing 777-300एफबेड़े को ही चलाने की मंजूरी है। देशों द्वारा दी जाने वाली एविएशन मंजूरीयाँ काफी अलग-अलग हो सकती हैं: कुछ मंजूरीयाँ एयरलाइन के आधार पर जारी की जाती हैं, जबकि कुछ खास विमानों के प्रकारों या यहाँ तक कि अलग-अलग विमानों के टेल नंबरों के लिए होती हैं।



दिल्ली में यात्रियों की मदद का इंतजाम

एयरलाइन ने आगे कहा कि दिल्ली में ग्राउंड टीमों ने यात्रियों के लिए मदद का इंतजाम किया, जिसमें होटल में ठहरने की व्यवस्था भी शामिल थी, और यह पक्का करने की कोशिश की कि वे जल्द से जल्द अपनी मंजिल तक पहुँच सकें। यह फ्लाइट आज सुबह सभी यात्रियों के साथ रवाना हो गई। इस घटना से लागत पर काफी असर पड़ने की उम्मीद है, क्योंकि एक Boeing 777 आम तौर पर, उड़ान की स्थितियों के आधार पर, हर घंटे लगभग आठ से नौ टन ईंधन खर्च करता है।

बीच रास्ते से बुलाया

वापिस

इस बात का एहसास होने के बाद, विमान को बीच रास्ते से ही दिल्ली वापस बुला लिया गया। यह शाम लगभग 7:19 बजे सुरक्षित रूप से उतर गया, जो उड़ान भरने के लगभग नौ घंटे बाद का समय था। सभी यात्री और कर्मी बिना किसी घटना के विमान से उतर गए। एयर इंडिया ने एक बयान में, वापसी की वजह एक ऑपरेशनल दिक्कत बताई और कहा कि यह फैसला स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के मुताबिक लिया गया था। एयरलाइन ने कहा, विमान सुरक्षित रूप से उतर गया, और सभी यात्री और कर्मी विमान से उतर गए। हमें अपने मेहमानों को हुई असुविधा के लिए खेद है।



पेज 06 अवैध कब्जों को लेकर कई बार मंत्री से मिलने का...

निगम जोन-डी के इलाकों में अवैध निर्माण और स्मार्ट सिटी फंडों का मिसयूज होने के आरोप, PMIDC ने निगम कमिश्नर को जांच के लिए आदेश

लुधियाना/यूटर्न/20 मार्च। नगर निगम के जोन-डी के अधीन आते इलाकों को केंद्र सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी परियोजना के अधीन लिया था। जिसके चलते कई हजार करोड़ रुपये के फंड भी जारी हुए। लेकिन इन फंड का मिसयूज होने और जोन-डी के अधीन आते इलाकों में धड़ल्ले से अवैध निर्माण व कब्जे हुए।

जिसके चलते इस मामले में पंजाब म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी द्वारा संज्ञान ले लिया गया है। उनकी ओर से निगम कमिश्नर कम स्मार्ट सिटी परियोजना की सीईओ नीरू कत्याल को नोटिस जारी किया गया है। जिसमें जोन-डी के अधीन आते इलाकों में हो रहे अवैध निर्माण, कब्जे और स्मार्ट सिटी फंड का गलत इस्तेमाल होने पर जांच करने और एक्शन लेने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार आम आदमी पार्टी के नेता और समाजसेवी रविंद्रपाल सिंह घई द्वारा लगातार जोन-डी और हल्का वेस्ट में अवैध निर्माण, सड़कों पर कब्जे होने और स्मार्ट सिटी फंड का गलत इस्तेमाल होने के आरोप लगाए जा रहे



मल्हार रोड पर वाहनों की रॉन्ग पार्किंग



छुटभैया नेता करवा रहे अवैध निर्माण

बता दें कि घुमारमंडी, कॉलेज रोड और रानी झांसी रोड पर धड़ल्ले से अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। चर्चा है कि कुछ छुटभैया नेताओं द्वारा यह इललीगल कार्य किए जा रहे हैं। वहीं रविंदर पाल सिंह घई द्वारा भी अपनी शिकायत में मल्हार रोड, साउथ सिटी और फिरोजपुर रोड पर गैर कानूनी निर्माण होने के आरोप लगाए हैं। चर्चा है कि निगम अधिकारियों द्वारा नेताओं के साथ मिलकर मोटी रिश्वत लेने के बाद यह निर्माण करवाए हैं।

मल्हार रोड पर करोड़ों रुपये कर डाले खराब

वहीं घई द्वारा मल्हार रोड पर स्मार्ट सिटी फंड की 100 करोड़ से अधिक की राशि खराब करने के आरोप लगाए गए हैं। जहां पर पार्किंग साइट बनाने की जगह वहां के शोरूम मालिकों को सुविधा देने के लिए सड़क पर ही 5 से 7 फीट चौड़े फुटपाथ बना दिए गए। जिसके चलते अब शोरूम मालिक व उनके ग्राहक फुटपाथ पर रॉन्ग पार्किंग कर रहे हैं। जिससे सड़क पर हर समय ट्रैफिक जाम लगा रहता है। इसी तरह लीडरों द्वारा अफसरों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने के लिए केंद्र से स्मार्ट सिटी फंड के नाम पर करोड़ों रुपये ले लिए, लेकिन खर्च नहीं किए। अगर कहीं खर्च किए तो लोगों को दुविधा में डाल दिया।

थे। उन्होंने इस संबंधी सीएम पंजाब, पंजाब म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी, लोकल बॉडी विभाग और निगम कमिश्नर को शिकायतें की थी। जिसके बाद पीएमआईडीसी द्वारा मामले में एक्शन लिया गया है।

कैबिनेट मंत्री अरोड़ा ने शहर को दी 1.74 करोड़ के विकास परियोजनाओं की सौगात, शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल सुविधाओं पर सरकार का फोकस



लुधियाना/यूटर्न/20 मार्च। कैबिनेट मंत्री Sanjeev Arora ने विकास को नई गति देते हुए करीब 1.74 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य शहर में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और युवाओं को खेलों की ओर प्रोत्साहित करना है।

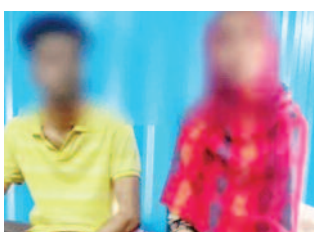
मुख्य आकर्षण सिविल अस्पताल के पीछे बनाए गए बहुउद्देश्यीय स्पोर्ट्स पार्क का रहा, जिसे लगभग 91 लाख रुपये की लागत से तैयार किया गया है। पहले यह स्थान खंडहर और कचरा फेंकने की जगह था, जिसे अब आधुनिक खेल परिसर में बदल दिया गया है।



यहां क्रिकेट, पिकलबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा, जैमल सिंह रोड पर स्थित विश्वकर्मा पार्क का 38 लाख रुपये की लागत से पुनर्विकास किया गया है, जहां खेल सुविधाओं के साथ-साथ लोगों के लिए बेहतर वातावरण तैयार किया गया है।

वहीं, ढोलेवाल क्षेत्र में करीब 45 लाख रुपये की लागत से सीवरेज लाइन बिछाने का कार्य भी शुरू किया गया है। Bhagwant Singh Mann के नेतृत्व में सरकार शहर में लोक-केन्द्रित विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और जीवन स्तर मिल सके।

प्रेमी से मिलने एमपी से लुधियाना पहुंची नाबालिग लड़की, स्नैपचैट पर हुआ प्यार, कोर्ट में बोली- फ्रेंड है



लुधियाना/यूटर्न/20 मार्च। मध्यप्रदेश की एक नाबालिग लड़की स्नैपचैट पर हुए प्यार के चक्कर में लुधियाना पहुंच गई। वह लुधियाना रेलवे स्टेशन पहुंची। यहां किसी के मोबाइल से प्रेमी से संपर्क किया। फिर प्रेमी उसे अपने साथ ले गया। करीब 4 महीने तक वह उसके साथ भी रही। उधर, एमपी में परिवार ने बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जिसके बाद मध्यप्रदेश पुलिस ने करीब एक हफ्ते पहले उसे लुधियाना में ट्रेस किया और दोनों को पकड़कर ले गई। जिसके बाद इस पूरे मामले का लुधियाना में खुलासा हुआ। हालांकि पुलिस ने जब उसे कोर्ट में पेश किया तो लड़की ने कोर्ट में कहा कि मैं जब गई थी तब नाबालिग थी लेकिन अब बालिग हो चुकी हूँ। युवक मेरा फ्रेंड है। इसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। मुझे अलग रूम में रखा।

अंगदान जागरूकता को नई दिशा: पीजीआईएमईआर सम्मेलन में भावुक कहानियों ने जगाई उम्मीद



चंडीगढ़, यूटर्न, 20 मार्च। पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) में आयोजित 7वें 'ट्रांसप्लांट सर्जरी ऑरेशन' और इंडियन सोसाइटी ऑफ ट्रांसप्लांट सर्जन्स के राष्ट्रीय सम्मेलन ने अंगदान के प्रति जागरूकता को नई ऊर्जा दी। देश-विदेश के विशेषज्ञों, डॉक्टरों और परिवारों ने इसमें भाग लेकर ट्रांसप्लांट क्षेत्र की प्रगति और मानवीय पहलुओं पर चर्चा की। मुख्य वक्ता प्रो. प्रांजल मोदी ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि टीमवर्क और निरंतर प्रयासों से सैकड़ों लोगों को नया जीवन मिला है। उन्होंने रोबोटिक किडनी ट्रांसप्लांट को भविष्य की दिशा बताया। सम्मेलन में विशेषज्ञों ने बढ़ती मरीज संख्या के बीच अंगदान को बढ़ावा देने की जरूरत पर जोर दिया।

उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी ने कैबिनेट का विस्तार किया, पांच विधायकों को शामिल किया

चंडीगढ़/यूटर्न/20 मार्च। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को अपनी कैबिनेट का विस्तार किया, जिसमें पांच विधायकों ने यहां लोक भवन में मंत्री पद की शपथ ली।

अधिकारियों ने बताया कि नए मंत्रियों खजान दास, भरत सिंह चौधरी, मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा और राम सिंह कैड़ा के शामिल होने के साथ ही उत्तराखंड कैबिनेट की संख्या बढ़कर अपनी अधिकतम सीमा 12 तक पहुंच गई है। लोक भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह के दौरान राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। खजान दास देहरादून की राजपुर रोड विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि भरत सिंह चौधरी रुद्रप्रयाग, मदन कौशिक हरिद्वार, प्रदीप बत्रा रुड़की और राम सिंह कैड़ा भीमताल का प्रतिनिधित्व करते हैं।

चौधरी, बत्रा और कैड़ा को पहली बार मिला सेवा का मौका... चौधरी, बत्रा और कैड़ा को पहली बार मंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिला है, जबकि दास और कौशिक पहले भी कैबिनेट में रह चुके हैं। कैबिनेट का यह विस्तार गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्रों के बीच संतुलन बनाने के साथ-साथ मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के प्रयास को दर्शाता है, अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों से पहले इस कदम को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सीएम ने दी बधाई... नए मंत्रियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी टीम राज्य के विकास और जनसेवा के लिए मिलकर काम करेगी। धामी ने कहा, हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ राज्य के सबसे दूरदराज के कोने में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर मिलें। हम सभी टीम भावना के साथ काम करेंगे और राज्य की जनता की सेवा के लिए समर्पित रहेंगे। धामी के अलावा, उनके कैबिनेट सहयोगी और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे।



हरियाणा में जल जीवन मिशन-2.0 के लिए केंद्र व राज्य के बीच हुआ एमओयू

हरियाणा/ यूटर्न/20 मार्च। हरियाणा में जल आपूर्ति व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए जल जीवन मिशन के दूसरे चरण को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। इस संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वर्युअल रूप से शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल जीवन मिशन-2.0 में केवल पानी की सप्लाई ही नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता, स्थिरता और दीर्घकालिक प्रबंधन पर भी ध्यान दिया जाएगा। इसके तहत जल भंडारण टैंकों का आधुनिकीकरण, शेष घरों को पाइपलाइन से जोड़ना और नूंह, पलवल व महेंद्रगढ़ जैसे जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में विशेष परियोजनाएं लागू की जाएंगी। इन योजनाओं पर करीब



File Photo

3000 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने बताया कि पहले चरण में राज्य ने 100% ग्रामीण घरों तक नल कनेक्शन पहुंचाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। इससे महिलाओं को दूर से पानी लाने की परेशानी से मुक्ति मिली है और जीवन स्तर में सुधार हुआ

है। केंद्रीय मंत्री सी.आर. पाटिल ने हरियाणा सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन-1 की सफलता के बाद अब दूसरे चरण को और प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे हर घर तक स्वच्छ जल पहुंचाने का लक्ष्य और मजबूत होगा।

मत्स्य पालन से जुड़ी कई सेवाएं राइट टू सर्विस के दायरे में नई सेवाओं के लिए समय-सीमा निर्धारित



हरियाणा/ यूटर्न/20 मार्च। हरियाणा सरकार ने नागरिकों को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मत्स्य पालन से जुड़ी कई सेवाओं को हरियाणा अधिकार सेवा अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित किया है। इस संबंध में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने अधिसूचना जारी की।

नई व्यवस्था के तहत सघन मत्स्य पालन विकास कार्यक्रम में लोडिंग ऑटो, फोर व्हीलर और ट्रॉली सहित मिनी ट्रैक्टर पर मिलने वाली सब्सिडी अब 40 दिनों के भीतर दी जाएगी। वहीं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम,

न्यूक्लियस प्रजनन केंद्र (ठंडु), स्टार्टअप, इन्क्यूबेटर, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण जैसी गतिविधियों के लिए भी सब्सिडी शामिल की गई है। इसके अलावा सजावटी मछली इकाइयों, बूड बैंक, मनोरंजक मत्स्य पालन, ई-मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, कोल्ड स्टोरेज आधुनिकीकरण और मत्स्य उत्पादों के मूल्य वर्धन से जुड़े उद्यमों को भी इस दायरे में लाया गया है। इन सभी सेवाओं के लिए 50 दिनों की समय-सीमा तय की गई है। जिला मत्स्य पालन अधिकारी को नामित अधिकारी, उप-निदेशक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और निदेशक मत्स्य पालन को द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी बनाया गया है।

सीवरेज के गंदे पानी ने घरों में दी दस्तक, वार्ड 10 के निवासियों का फूटा गुस्सा, नगर परिषद के खिलाफ किया प्रदर्शन

-चरणजीत सिंह चन्न-
जगरांव/यूटर्न/20/मार्च। शहर के रायकोट रोड स्थित गांधी नगर (वार्ड नंबर 10) में पिछले एक महीने से बदहाल सीवरेज व्यवस्था ने स्थानीय निवासियों का जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। शुरुआत को स्थिति तब बेकाबू हो गई जब सड़कों और नालियों में बहने वाला सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों के अंदर तक घुसने लगा। इस गंभीर जलभराव और प्रशासनिक

अनदेखी से आक्रोशित होकर मोहल्लेवासियों ने स्थानीय पार्षद रमेश कुमार सहोता (मेर्षी) के नेतृत्व में नगर कौंसिल के खिलाफ जोरदार धरना-प्रदर्शन किया।

पिने के पानी में मिल रहा सीवरेज, मंडराया बीमारियों का खतरा...स्थानीय निवासियों- बलदेव सिंह, जगतार सिंह, बूटा सिंह, छिंदर सिंह, गुरचरण सिंह और मीता सिंह ने अपनी परेशानी साझा करते हुए बताया कि गर्मी के मौसम की शुरुआत के साथ ही इलाके में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। सबसे

फरीदाबाद के बिजली बिलिंग प्रकरण में आयोग के निर्देश, उपभोक्ता को 5,000 रुपये मुआवजा देने के आदेश

हरियाणा/ यूटर्न/20 मार्च। हरियाणा राइट टू सर्विस कमीशन ने जिला फरीदाबाद में बिजली बिलिंग प्रकरण में उपभोक्ता करण सिंह खत्री को 5,000 रुपये मुआवजा देने के निर्देश दिए हैं। यह राशि संबंधित अधिकारियों से वसूली जाएगी। आवेदक ने 01 अगस्त 2024 को अस्थायी बिजली कनेक्शन लिया था और इस दौरान औसत आधार पर लगभग 2,500 रुपये प्रति माह के बिल नियमित रूप से चुका दिए। बाद में 19 जनवरी 2026 को 01 अगस्त 2024 से 15 जनवरी 2026 तक के लिए 15,833 रुपये का एकमुश्त बिल जारी किया गया। इसके विरोध में 21 जनवरी 2026 को शिकायत दर्ज करवाई गई और नियमानुसार प्रथम एवं द्वितीय अपील प्रक्रिया अपनाई गई। आयोग ने अपने आदेश में



कहा कि वास्तविक विद्युत खपत का भुगतान आवश्यक है, लेकिन लंबे समय तक औसत बिलिंग के बाद एकमुश्त राशि आने पर उपभोक्ता की सुविधा का ध्यान रखना जरूरी है। भविष्य में अधिकारियों को किस्तों में भुगतान जैसी व्यवस्था पर विचार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। हरियाणा राइट टू सर्विस एक्ट, 2014 की धारा 17(1)(ह) के तहत अधिकतम अनुमन्य 5,000 रुपये का मुआवजा दिया गया है। अधिकारी को 13 अप्रैल 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

चिंताजनक बात यह है कि सीवरेज का दूषित पानी अब पेयजल आपूर्ति की पाइपलाइनों में भी मिल रहा है। इसके चलते पानी पीने लायक तो दूर, दैनिक कार्यों में इस्तेमाल करने योग्य भी नहीं रह गया है। लोगों का कहना है कि स्कूली बच्चों और नौकरीपेशा लोगों को रोजाना इसी दुर्गन्धयुक्त पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे इलाके में महामारी फैलने का डर बना हुआ है।

अधिकारियों का घेराव और तत्काल सफाई का आदेश...धरने की सूचना मिलते ही स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस प्रशासन और नगर परिषद

के अधिकारी मौके पर पहुंचे। जब नगर परिषद के कार्यकारी प्रधान कंवरपाल वहां आए, तो उन्हें लोगों के तीखे सवाल और भारी रोष का सामना करना पड़ा। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट लहजे में पूछा कि जब वे नगर परिषद को समय पर सभी टैक्स चुका रहे हैं, तो बुनियादी सुविधाओं में उनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? लोगों के उग्र होते गुस्से को देखते हुए और स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए, अधिकारियों ने तुरंत सफाई कर्मचारियों की टीमों मौके पर बुलाई और जलभराव की निकासी का काम शुरू करवाया गया।

मोहाली में नगर निगम टीम पर हमले में जमानत: आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास का सबूत नहीं, विदेश जाने को कोर्ट की अनुमति जरूरी

पंजाब/ यूटर्न/20 मार्च। मोहाली की एक अदालत ने अहम फैसला सुनाते हुए नगर निगम टीम पर हमले के मामले में आरोपी



गुरमीत सिंह उर्फ काला और गुरप्रीत सिंह को छह साल बाद नियमित जमानत दे दी है। यह मामला 4 सितंबर 2020 को गांव मटौर का है, जब

आवारा पशुओं को पकड़ने गई टीम पर हमला हुआ था। बुधवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में जमानत याचिका दायर की गई थी, जिसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के तहत पहली अर्जी बताया गया। कोर्ट ने राज्य को नोटिस जारी कर पुलिस रिकॉर्ड मंगवाया। एफआईआर में आरोप था कि आरोपियों ने टीम पर हमला किया, जबकि बचाव पक्ष ने इसे झूठा मामला बताया। अभियोजन पक्ष ने गंभीर आरोपों का हवाला देते हुए जमानत का विरोध किया और गवाहों को प्रभावित करने की आशंका जताई। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि हथियारों या चोटों का ठोस विवरण उपलब्ध नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह रही कि धारा 307 (हत्या के प्रयास) को साबित करने के लिए कोई मेडिकल रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। कोर्ट ने इसे 'खाली दावा' मानते हुए आरोपियों को 80-80 हजार रुपये के जमानत बांड पर रिहा करने का आदेश दिया।

समाधान शिविर निपटान में फतेहाबाद बना प्रदेश में नंबर वन



हरियाणा/ यूटर्न/20 मार्च। फतेहाबाद जिला समाधान शिविरों में प्राप्त शिकायतों के त्वरित, पारदर्शी और प्रभावी निपटान में पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। इस उपलब्धि पर हरियाणा सरकार में श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव रंजन ने समीक्षा बैठक के दौरान जिला प्रशासन की सराहना की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में उन्होंने डीसी डॉ. विवेक भारती और उनकी टीम को बधाई देते हुए कहा कि फतेहाबाद प्रशासन शिकायतों को गंभीरता से लेकर उनका समयबद्ध समाधान कर रहा है, जो अन्य जिलों के लिए एक मिसाल है। उन्होंने यह भी बताया कि समाधान प्रकोष्ठ पोर्टल पर वर्ष 2024 की कोई भी शिकायत लंबित नहीं है।

डीसी डॉ. विवेक भारती ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविरों में आई शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निपटान किया जाए। उन्होंने वर्ष 2025 की लंबित शिकायतों को अगले 15 दिनों में खत्म करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, खारिज की गई शिकायतों की कारण सहित रिपोर्ट दो दिन में प्रस्तुत करने को कहा गया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अधिकारियों को अन्य पोर्टलों पर दर्ज शिकायतों के शीघ्र समाधान के निर्देश भी दिए गए हैं।



पेज 12 तख्त श्री दमदमा साहिब के लिए 1,120 करोड़ रुपये...

सुखना कैचमेंट एरिया में अवैध निर्माण पर 'दोहरी मार', बिजली कनेक्शन पर राहत से हाई कोर्ट का इनकार

अजीत झा
चंडीगढ़/यूटर्न/20 मार्च। सुखना कैचमेंट एरिया और सुखना विडलाइफ संक्रुअरी के इको-सेंसिटिव जोन (एरे) में हुए अवैध निर्माणों पर कानूनी और प्रशासनिक शिकंजा कसता जा रहा है। केंद्र सरकार के सख्त निर्देशों और न्यायपालिका के कड़े रुख के बीच अब इन इलाकों में रहने वाले लोगों पर 'दोहरी मार' पड़ती नजर आ रही है।

केंद्र सरकार का 1

किलोमीटर एरे नियम

मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फारेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 3 दिसंबर 2025 को पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि अभयारण्य के चारों ओर कम से कम 1 किलोमीटर का इको-सेंसिटिव जोन अधिसूचित किया जाए। यह निर्देश 2 मार्च 2026 के हाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप है। इस फैसले से सुखना एनक्लेव, ट्रिब्यून कॉलोनी, कांसल, कैबवाला, नयागांव और सकेतड़ी जैसे इलाकों में बने हजारों मकानों पर खतरा मंडराने लगा है।



बिजली निगम ने जताई असमर्थता

पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने भी कोर्ट में स्पष्ट किया कि पूर्व के अंतरिम आदेशों के चलते वह इन क्षेत्रों में बिजली, पानी और सीवरेज जैसी सुविधाएं देने में असमर्थ है। निगम ने कांसल क्षेत्र के निवासियों के लिए अस्थायी बिजली कनेक्शन की अनुमति मांगी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया।

चीफ जस्टिस की सख्त टिप्पणी

मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सख्त टिप्पणी करते हुए पूछा, हज़ील को और कितना सुखाओगे? अदालत ने बिल्डर माफिया और कथित राजनीतिक संरक्षण पर भी सवाल उठाए हैं, जिससे संबंधित अधिकारियों पर भी कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है।

निवासियों में दहशत, प्रॉपर्टी बाजार प्रभावित...प्रशासनिक सख्ती के चलते इन क्षेत्रों में नई सरकारी सुविधाएं पूरी तरह बंद हैं। कई मध्यमवर्गीय परिवार, जिन्होंने इन इलाकों में निवेश किया था, अब नुकसान की आशंका से चिंतित हैं। लोग अपनी संपत्तियां बेचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कानूनी अनिश्चितता के कारण खरीदार नहीं मिल रहे।

जल्द आ सकता है बड़ा फैसला...पुरा मामला अब डिवीजन बेंच के समक्ष लंबित है और आने वाले समय में इस पर बड़ा फैसला आने की संभावना है, जिससे इन अवैध निर्माणों का भविष्य तय होगा।

हाई कोर्ट ने बिजली कनेक्शन पर राहत देने से किया इनकार

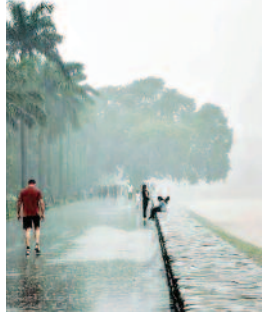
हाल ही में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहन बंसल की अदालत ने अवैध कॉलोनियों में बिजली कनेक्शन देने को लेकर कोई सीधा आदेश देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने 'जीवन के अधिकार' (अनुच्छेद 21) के तहत बिजली जैसी मूलभूत सुविधा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने कहा कि मामला पहले से डिवीजन बेंच के समक्ष विचाराधीन है। ऐसे में इस स्तर पर हस्तक्षेप उचित नहीं होगा और याचिकाकर्ताओं को डिवीजन बेंच के समक्ष जाने को कहा गया।

'लिविंग एंटिटी' आदेश का असर

हाई कोर्ट पहले ही सुखना झील को हज़ीवित इकाई घोषित कर चुका है और 2011 के बाद हुए निर्माणों को हटाने के निर्देश दे चुका है, साथ ही प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की बात भी कही गई थी। अब इस आदेश के सख्ती से लागू होने की संभावना जताई जा रही है।

चंडीगढ़ में मौसम ने ली करवट, बारिश और ठंडी हवाओं से मार्च में लौटी सर्दी; ऑरेंज अलर्ट जारी

चंडीगढ़/यूटर्न/20 मार्च। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी और पंजाब-चंडीगढ़ में पिछले दो दिनों से रुक-रुक कर हो रही बारिश के चलते मौसम ने अचानक करवट ले ली है। वीरवार सुबह से शहर में लगातार बारिश होने से ठंडक बढ़ गई और दिनभर आसमान में बादल छाए रहे। ठंडी हवाओं के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे मार्च के महीने में एक बार फिर हल्की सर्दी का अहसास हुआ।



तापमान में 8 डिग्री की गिरावट

मौसम विभाग के अनुसार, बारिश और ठंडी हवाओं के प्रभाव से वीरवार को अधिकतम तापमान में करीब 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 20.8 डिग्री और न्यूनतम 14.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिन और रात के तापमान में केवल 6 डिग्री का अंतर रहा, जो सामान्य से कम है। पिछले 24 घंटों में शहर में 4.8 एमएम बारिश दर्ज की गई।

शुक्रवार के लिए ऑरेंज अलर्ट

मौसम विभाग ने शुक्रवार के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक, शहर और आसपास के इलाकों में बारिश जारी रह सकती है, साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

मौसम बदलने की वजह

विशेषज्ञों के अनुसार, राजस्थान के ऊपर बना मौसम तंत्र पश्चिमी राजस्थान की ओर खिसक गया है और जमीन से थोड़ा ऊपर सक्रिय है। इसके साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है, जो ऊपरी स्तर पर हवाओं में हलचल पैदा कर रहा है। हरियाणा के ऊपर बना सिस्टम अब कमजोर पड़ चुका है, जिसके चलते उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखा जा रहा है।

आने वाले दिनों का पूर्वानुमान

- शुक्रवार : बारिश और तेज हवाएं, अधिकतम 21°C, न्यूनतम 14°C
 - शनिवार : मौसम साफ, अधिकतम 23°C, न्यूनतम 13°C
 - रविवार : आंशिक बादल, अधिकतम 25°C, न्यूनतम 14°C
- मौसम विभाग ने बदलते मौसम के बीच लोगों को स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है।

सेक्टर-9 मर्डर केस: पोस्टमॉर्टम शुरू, गैंगस्टर कनेक्शन और इंटरस्टेट ऑपरेशन का खुलासा

अजीत झा,
चंडीगढ़/यूटर्न/20 मार्च। सेक्टर-9 में जिम के बाहर प्रॉपर्टी डीलर चमनप्रीत सिंह उर्फ चिनी की हत्या के मामले में जांच तेज हो गई है। परिवार की सहमति के बाद शुक्रवार को पीजीआई में पोस्टमॉर्टम शुरू कर दिया गया।

कैथल मुठभेड़ में आरोपी

गिरफ्तार
मामले में बड़ा ब्रेकथू देते हुए 19 मार्च को पंजाब पुलिस ने हरियाणा के कैथल में मुठभेड़ के बाद दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान फिरोजपुर निवासी राजन उर्फ पीयूष पहलवान और नवांशहर निवासी प्रीतम शाह के रूप में हुई है। मुठभेड़ के दौरान दोनों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए पीजीआई चंडीगढ़ लाया गया है।

परिवार को पुलिस का भरोसा

मृतक के परिजनों ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पोस्टमॉर्टम के लिए सहमति दी। पुलिस ने परिवार को आश्वस्त किया है कि मामले में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क और गैंगस्टर कनेक्शन की गहराई से जांच कर रही है, जिससे इस हत्याकांड से जुड़े अन्य लोगों का भी खुलासा हो सकता है।



मृतक चरणप्रीत उर्फ चिनी



गैंगस्टर लकी पटियाल की साजिश

पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस हत्याकांड की साजिश गैंगस्टर लकी पटियाल ने रची थी। जांच में सामने आया है कि आरोपी जिग ऐप के जरिए गैंगस्टर के संपर्क में थे और विदेश से भी उनके निर्देश मिल रहे थे। बताया जा रहा है कि एक आरोपी जनवरी में मलेशिया से भारत आया था।

वारदात से पहले लंबी रेकी

पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपियों ने वारदात से पहले कई दिनों तक चंडीगढ़, मोहाली और कैथल में रहकर रेकी की। उन्हें पीड़ित की दिनचर्या की पूरी जानकारी थी और उसी के आधार पर जिम के बाहर घात लगाकर हत्या को अंजाम दिया गया।

हथियार और भागने की प्लानिंग पहले से तैयार

सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने सरहद पार से हथियार मंगवाए और उनका इस्तेमाल करने की प्रैक्टिस भी की। वारदात के बाद आरोपी बाइक से मोहाली की ओर भागे और रास्ते बदलते हुए हरियाणा पहुंच गए। पुलिस ने तकनीकी निगरानी के जरिए करीब 130 किलोमीटर तक उनका पीछा कर कैथल में ट्रेस किया।

संयुक्त ऑपरेशन में हुई गिरफ्तारी

पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और हरियाणा पुलिस की एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपियों को घेर लिया। सरेंडर के लिए कहने पर आरोपियों ने फायरिंग की, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में उन्हें काबू कर लिया गया।

अफ्रीकी दूतावास (साउथ अफ्रीकन हाई कमीशन) में काउंसलर श्री सेडुला माशुदुबेले मामाबोलो के साथ राजेश बाघा और उदय सूद की एक बैठक हुई

दलजीत अज्जोहा

नई दिल्ली/यूटर्न/20 मार्च। नई दिल्ली स्थित दक्षिण अफ्रीकी दूतावास



(साउथ अफ्रीकन हाई कमीशन) में काउंसलर श्री सेडुला माशुदुबेले मामाबोलो के साथ एक शानदार बैठक हुई। इस बैठक में राजेश बाघा पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व अध्यक्ष, भाजपा पंजाब (भारत) के उपाध्यक्ष, पाथवे ग्लोबल

अलायंस के मुख्य संरक्षक और ब्रिटिश रविदासिया हेरिटेज फाउंडेशन (यूनाइटेड किंगडम) की भारतीय शाखा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पाथवे ग्लोबल अलायंस के महासचिव श्री उदय सूद भी उपस्थित थे और दक्षिण अफ्रीकी में सतगुरु रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती पर होने वाले आने वाले कार्यक्रमों की तैयारी के लिए नई दिल्ली में खास मीटिंग हुई राजेश बाघा ने जानकारी देते हुए कहा कि सतगुरु रविदास महाराज जी की 650वीं जयंती पर होने वाले आने वाले कार्यक्रमों की तैयारी के लिए एक जरूरी मीटिंग में भारत के सोशल लीडर्स ने हिस्सा लिया।

जोन-डी बाहर सच्चा यादव का कॉफी विद संजीव अरोड़ा कार्यक्रम आयोजित

अवैध कब्जों को लेकर कई बार मंत्री से मिलने का प्रयास, लेकिन पीए बोला - छोड़ो, गरीबों को रोटी खाने दो

राजदीप सिंह सैनी

लुधियाना/यूटर्न/20 मार्च। लुधियाना में लगातार हो रहे अवैध कब्जे, टूटी सड़के और एक्रोचमेंट को लेकर समाजसेवी कुमार गौरव उर्फ सच्चा यादव द्वारा लोकल बांडी मंत्री संजीव अरोड़ा से मिलने का प्रयास किया गया। लेकिन हर बार उनके पीए आदित्य द्वारा बहानेबाजी करके टाल दिया गया। जिसके चलते सच्चा यादव द्वारा शुक्रवार को नगर निगम के जोन-डी ऑफिस के बाहर कॉफी विद मंत्री संजीव अरोड़ा कार्यक्रम आयोजित कर अनोखे ढंग से अपना विरोध जाहिर किया गया। हालांकि उनकी तरफ से मंत्री को कॉफी का न्यौता दिया गया था। लेकिन वह नहीं आए तो सच्चा यादव द्वारा कुर्सी पर उनकी फोटो रखकर अपनी शिकायतें दर्ज करवाई। इस दौरान शहर की टूटी सड़के, सरकारी जमीनों पर कब्जे, एक्रोचमेंट, डेयरियों के नाम पर करोड़ों रुपए की बबार्दी, ताजपुर रोड पर कई लाख टन कूड़े के पहाड़, गोबर घोटाला, कूड़ा लिफ्टिंग घोटाला, इंडस्ट्री की राख से प्रदूषण फैलने से सांस लेने की समस्या समेत तमाम मुद्दे उठाए।

अवैध कब्जों पर मंत्री के पीए का जवाब झ गरीबों को रोटी खाने दो



वहीं सच्चा यादव ने कहा कि हैबोवाल व फिरोजगांधी मार्केट में लगातार अवैध कब्जे हो रहे हैं। हैबोवाल में लॉर्ड महावीर होम्योपैथिक कॉलेज के बाहर आप नेता द्वारा दर्जनों की गिनती में रेहड़ियां लगाकर अवैध कब्जे कराए गए। जहां ट्रैफिक जाम होने के साथ साथ कॉलेज स्टूडेंट्स की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। करीब दो महीने पहले तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने मंत्री संजीव अरोड़ा से मीटिंग करने के लिए कॉल की। पीए आदित्य ने फोन उठाया और मीटिंग का कारण पूछा। जिस पर आदित्य ने मीटिंग के लिए समय तो नहीं दिया बल्कि आगे से राय दे दी कि फिर क्या हुआ कब्जे हुए हैं तो, गरीबों को रोटी खाने दीजिए। जिस पर सच्चा यादव ने कहा कि जब निगम द्वारा चौड़ा बाजार और

गिल रोड पर रेहड़ियां हटाई जाती है तो वे क्या करोड़पति हैं। वह भी तो गरीब ही होते हैं। अपने लीडरों ने रेहड़ियां लगाई तो ठीक है क्या।

जनता द्वारा चुने गए लीडर को भी मिलना मुश्किल

वहीं सच्चा यादव ने कहा कि उन्होंने फिर पीए आदित्य से फोन करके मंत्री अरोड़ा से मिलने का समय मांगा। लेकिन उन्होंने मिलने के लिए भी कारण पूछा। जब एजेंडे बताए तो भी समय नहीं दिया गया। सच्चा यादव का कहना है कि पीए आदित्य के मुताबिक मंत्री अति व्यस्त है। बेशक वे मंत्री अरोड़ा को पूरा पंजाब देखना होता है, लेकिन जिस शहर से वे जीतकर मंत्री बने हैं, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लीडरों को जनता द्वारा चुना जाता है। लेकिन उनके पीए ही जनता को मंत्री से मिलने नहीं देते।

कभी समय था, जब हल्का वेस्ट सबसे खूबसूरत था

खराब सड़कों से लोग गिरकर मर रहे हैं, जखमी हो रहे हैं। शहर की कोई भी सड़क दुरुस्त नहीं है। कुमार गौरव ने कहा कि कभी समय था, जब वेस्ट सबसे खूबसूरत हल्का था। लेकिन आज उसकी हालत दर्दनीय है। इसी तरह ढोलेवाल की विश्वकर्मा कॉलोनी में सड़के टूटी पड़ी हैं। विपक्ष के लीडर पार्श्व बनकर भी नहीं सुन रहे और आप सरकार काम नहीं कर रही। ऐसे में लोग जाएं तो कहा जाए।

पेट्रोल और डीजल में रेट में बढ़ोतरी के कारण पेट्रोल पम्प पर लगी भीड़

सुनील पांडे
लुधियाना/यूटर्न/20 मार्च। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के पीछे मुख्य वजह अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और प्रीमियम फ्यूल में मिलाए जाने वाले एडिटिव्स की लागत बढ़ना माना जा रहा है। सामान्य पेट्रोल के मुकाबले यह पहले से ही 5 से 10 रुपए महंगा होता है। अब इस बढ़ोतरी के बाद यह अंतर और बढ़ जाएगा। इजरायल-ईरान के बीच चल रही जंग का असर अब



देश में दिखने लगा है। कच्चे तेल की आसमान छूती कीमतों के

बीच पेट्रोल और डीजल के दामों में एक के बाद एक इजाफा देखने को मिला है। पहले जहां पावर पेट्रोल के दाम 2 रुपए तक बढ़ गए और अब इंडस्ट्रियल डीजल भी 22 रुपए महंगा हो गया है।

आम जनता के लिए राहत की बात यह है कि बेस फ्यूल यानी सामान्य पेट्रोल और डीजल की कीमतों को नहीं छेड़ा गया है। तेल कंपनियों ने आखिरी बार मार्च 2024 में आम पेट्रोल-डीजल की कीमतों में 2 रुपए की कटौती की थी।

इयूक ने लॉन्च किया शानदार Summer Edit – 2026 कलेक्शन: रोजमर्रा के स्टाइल और कम्फर्ट को नया आयाम

लुधियाना/यूटर्न/20 मार्च। इयूक एक प्रमुख भारतीय कपड़ा और लाइफस्टाइल ब्रांड है, जो पूरे परिवार के लिए किफायती और स्टाइलिश फैशन उपलब्ध कराता है। वर्ष 1966 में स्थापित इस ब्रांड की समृद्ध विरासत है और यह अपनी भारतीय पहचान को बनाए रखते हुए वैश्विक फैशन ब्रांड बनने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। जैसे-जैसे मौसम गर्म होता है और हल्के व आरामदायक कपड़ों की जरूरत बढ़ती है, इयूक इंडिया लिमिटेड ने अपने बहुप्रतीक्षित समर एडिट इज़ 2026 कलेक्शन के लॉन्च की घोषणा की है। आधुनिक भारतीय उपभोक्ताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया यह कलेक्शन अंतरराष्ट्रीय फैशन ट्रेंड्स को आरामदायक और सांस लेने योग्य फैब्रिक्स के साथ जोड़ता है, जिससे रोजमर्रा की स्टाइलिंग और भी आसान हो जाती है। इसमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों



के लिए ट्रेंडी और आरामदायक कपड़ों की विस्तृत रेंज शामिल है। समर एडिट इज़ 2026 कलेक्शन को प्रीमियम कॉटन, प्राकृतिक और टेक्सचर्ड फैब्रिक्स से तैयार किया गया है, जो शरीर को ठंडक का एहसास देते हैं और तेज गर्मी में भी अधिकतम आराम सुनिश्चित करते हैं।

प्रीमियम पेट्रोल 2.35रु.
प्रति लीटर तक महंगा

हाय! अब तेरा
पेट भरू या
अपना...?



रुह से रुबरु



चारु नागपाल

रील बनाने की सनक और इंसानियत पर सवाल

आज के दौर में सोशल मीडिया पर रील बनाने की होड़ ने लोगों की सोच को काफी प्रभावित किया है। Instagram और Facebook जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रसिद्धि पाने की चाह में लोग कभी-कभी हदें पार कर देते हैं। हाल ही में बेंगलुरु में सामनेआई एक घटना ने सभी को हैरान कर दिया, जहां रील बनाने की सनक में एक व्यक्ति को बोरे में भरकर उसकी बेटी पार्सल के रूप में ले आई। यह घटना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि मानवता के लिए भी एक गंभीर चेतावनी है। प्रसिद्धि और लाइक्स पाने की चाह में लोग यह भूल जाते हैं कि उनके कार्यों का दूसरों पर क्या असर पड़ सकता है। ऐसी हरकतें समाज में भय और असुरक्षा का माहौल पैदा करती हैं। यह हरकत हमें यह भी बताती है कि हमारा समाज सोशल मीडिया पर झूठी प्रसिद्धि पाने के लिए कैसी कैसी काल्पनिक हरकतें करने से भी बाज नहीं आता। युवाओं को समझना चाहिए कि सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का साधन है, न कि खतरनाक स्टंट या गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार दिखाने का मंच। परिवार और शिक्षकों की भी जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को सही और गलत के बीच फर्क समझाएं। अंत में, हमें यह समझना होगा कि कुछ पल की प्रसिद्धि के लिए अपनी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालना बिल्कुल गलत है। जिम्मेदार नागरिक बनकर ही हम एक सुरक्षित और बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हैं।

कानूनी बात - निशांत प्रभाकर के साथ

Registry (Registration) की प्रक्रिया
कैसे होती है?

जब संपत्ति की बिक्री तय हो जाती है और रीं जी तैयार हो जाती है, तब अगला महत्वपूर्ण चरण होता है—
Registration, जिसे सामान्य भाषा में

“Registry” कहा जाता है।

Registry स्थानीय Sub-Registrar Office में की जाती है। इस प्रक्रिया में विक्रेता और खरीदार दोनों की उपस्थिति आवश्यक होती है।

दस्तावेज की जांच के बाद उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं और उसे आधिकारिक रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया जाता है।

Registration के दौरान पहचान प्रमाण, संपत्ति दस्तावेज और अन्य आवश्यक कागजात प्रस्तुत किए जाते हैं। इसके बाद दस्तावेज को सरकारी रिकॉर्ड में सुरक्षित रखा जाता है।

Registry का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संपत्ति लेन-देन पारदर्शी हो और भविष्य में किसी विवाद की स्थिति में आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध हो।

निष्कर्ष: Registry संपत्ति लेन-देन को कानूनी मान्यता देती है। बिना पंजीकरण के Sale Deed का प्रभाव सीमित रह सकता है।



निशांत प्रभाकर,
एडवोकेट

पांचवीं बार में संपन्न हुआ ब्लॉक समिति चुनाव

लॉटरी से 'आप' की किरणप्रीत कौर बनीं चेयरपर्सन

-चरणजीत सिंह चन्न्-

जगरांव/यूटर्न/20/मार्च। स्थानीय बी.डी.पी.ओ. (BDPO) कार्यालय में लंबे समय से लंबित ब्लॉक समिति के चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन का चुनाव आज अपने पांचवें प्रयास में आखिरकार संपन्न हो गया। दिलचस्प मुकाबले में दोनों गुटों (कांग्रेस और आम आदमी पार्टी) के सदस्यों की संख्या बराबर (12-12) रहने पर, नोडल अधिकारी-सह-एस.डी.एम. (SDM) मैडम उद्विंदरजीत कौर बराड़ ने पर्ची (ड्रॉ) सिस्टम के माध्यम से चुनाव प्रक्रिया को पूरा किया। इस ड्रॉ में आम आदमी पार्टी की महिला सदस्य किरणप्रीत कौर चेयरपर्सन और निर्दलीय सदस्य पवनप्रीत कौर वाइस-चेयरपर्सन चुनी गईं।



पारदर्शिता के साथ हुआ चुनाव-विधायिका माणुके

जीत के बाद खुशी व्यक्त करते हुए 'आप' विधायिका बीबी सरबजीत कौर माणुके ने कहा कि पिछले चार प्रयास किसी न किसी कारण से स्थगित होते रहे, लेकिन आज चुनाव पूरी पारदर्शिता और कानूनी मर्यादा के तहत संपन्न हुआ है। उन्होंने बताया कि ड्रॉ की पर्ची कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों द्वारा ही उठाई गई थी और वे स्वयं इस प्रक्रिया के दौरान कमरे से बाहर आ गई थीं, ताकि कोई पक्षपात का आरोप न लगा सके। उन्होंने आश्वासन दिया कि नवनिर्वाचित पदाधिकारी बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के विकास कार्य करेंगे।

कांग्रेस ने अकाली दल पर साधा निशाना

बी.डी.पी.ओ. कार्यालय के बाहर कांग्रेस के हलका इंचार्ज जगतार सिंह जग्गा हिस्सोवाल ने नतीजों पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने शिरोमणि अकाली दल पर निशाना साधते हुए कहा कि सुखबीर बादल दो दिन पहले जगरांव रैली में 'आप' की नीतियों को पंजाब विरोधी बता रहे थे, जबकि आज उन्हीं के सदस्य 'आप' के साथ मिलकर चेयरमैन बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यह साबित करता है कि अकाली दल और आम आदमी पार्टी अंदरखाते मिले हुए हैं।

अकाली दल लेगा एक्शन-एस.आर. कलेर: जब इस संबंध में शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक एस.आर. कलेर से फोन पर संपर्क किया गया, तो उन्होंने कहा कि असल में 'आप' और कांग्रेस आपस में मिले हुए हैं। उनके दो सदस्यों द्वारा 'आप' का साथ देने के सवाल पर कलेर ने अनभिज्ञता जताई। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि उनके सदस्यों ने 'आप' के पक्ष में वोट किया है, तो वे हाईकमान से बात कर उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए 'कारण बताओ' नोटिस (Show-cause notice) जारी करेंगे।

खुशी मनाया भी भूले कांग्रेसी: आम आदमी पार्टी की चेयर पर्सन बनने की वजह से कांग्रेस पार्टी के अहोदेदार और वर्कर कांग्रेस पार्टी की अप चेयर पर्सन बनने की खुशी तक मानना भूल गए। शायद उन्हें कांग्रेस पार्टी का साथ दे रही आजाद उम्मीदवार उप चेयरपर्सन बनाई गईं की इतनी खुशी नहीं हुई जितनी की आम आदमी पार्टी की चेयर पर्सन बनने का दुख लगा।

जालंधर में गैस किल्लत पर कैबिनेट मंत्री का आश्वासन: घरेलू सिलेंडरों की आपूर्ति बिना रुकावट होगी, कालाबाजारी पर सख्त करेंगे कार्रवाई

जालंधर/ यूटर्न/20 मार्च। मोहिंदर भगत ने जालंधर के निवासियों को भरोसा दिलाया है कि शहर में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रहेगी।

उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि गैस एजेंसियों की नियमित जांच की जाए और सप्लाई प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रखी जाए। मंत्री ने अधिकारियों



को स्पष्ट रूप से कहा कि सिलेंडरों के वजन और बुकिंग प्रक्रिया की

सख्ती से जांच की जाए, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए शहर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार हर घर तक समय पर गैस सिलेंडर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कालाबाजारी और अवैध जमाखोरी पर सख्त रुख अपनाते हुए मंत्री ने चेतावनी दी

कि ऐसे मामलों में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन ने एक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 9646222555 भी जारी किया है, जिस पर लोग शिकायत दर्ज करा सकते हैं। मंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराहट में अनावश्यक गैस सिलेंडर न खरीदें, क्योंकि शहर में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है।

5 अलग-अलग मामलों में 139 नशीली गोलियों के साथ 5 गिरफ्तार

-चरणजीत सिंह चन्न्-

जगरांव/यूटर्न/20/मार्च। लुधियाना देहाती पुलिस द्वारा साझा की गई दैनिक क्राइम रिपोर्ट से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इलाके में नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। देहाती पुलिस के अंतर्गत आते थाना जोधां, दाखा, सदर जगरांव, हटूर और सिटी रायकोट की पुलिस टीमों ने गश्त और चेकिंग के दौरान 5 आरोपियों को नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है।

प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इन मामलों का विवरण इस प्रकार है: पुलिस चौकी छपार (थाना जोधां): चौकी प्रभारी एएसआई जसपाल सिंह की टीम रछीन रोड छपार के पास मौजूद थी। इस दौरान गांव छपार की ओर से पैदल आ रहे मनजीत सिंह उर्फ सोनी को शक के आधार पर

रोका गया। पुलिस को देखकर उसने भागने की कोशिश की। तलाशी लेने पर उसकी पैंट की जेब से एक पारदर्शी लिफाफे में 40 खुली नशीली गोलियां बरामद हुईं।

थाना दाखा: एएसआई इंद्रजीत सिंह की पुलिस पार्टी जब दाना मंडी पुइंग के पास गश्त कर रही थी, तब सामने से आ रहे एक युवक ने पुलिस को देखकर घबराहट में अपनी जेब से एक लिफाफा पेड़ की जड़ों में फेंक दिया। पुलिस ने मुस्तैदी से सोनू सिंह निवासी तलवंडी नौ आबाद को काबू कर फेंके गए लिफाफे की जांच की, जिसमें से 40 नशीली गोलियां (20 लोमोटिल और 20 ट्रामाडोल) बरामद की गईं।

पुलिस चौकी चौकीमान (थाना सदर जगराओं): कासो (उअरड) ऑपरेशन के तहत चौकी प्रभारी एएसआई आत्मा सिंह को गुप्त सूचना मिली थी कि नशा बेचने का आदी वीरपाल सिंह उर्फ लौगा निवासी हांस कलां, नहर पुल कुलार साइड की तरफ आ रहा है। पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी कर उक्त आरोपी को 24 नशीली गोलियां सहित गिरफ्तार कर लिया।

थाना हटूर: थाना प्रभारी इंसपेक्टर कुलदीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस पार्टी दाना मंडी हटूर में सदिग्ध लोगों की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान शेड के नीचे खड़े एक युवक ने पुलिस की गाड़ी देखकर भागने की कोशिश की। पुलिस ने गुरविंदर सिंह उर्फ काली निवासी गांव चकर को काबू किया, जिसके पास से 20 नशीली गोलियां (ट्रामाडोल) बरामद हुईं।

थाना सिटी रायकोट: एएसआई कुलदीप सिंह की टीम को बस स्टैंड रायकोट पर गुप्त सूचना मिली थी कि अमनदीप सिंह उर्फ बांगडू निवासी मोहल्ला गुरुनानकपुरा दाना मंडी रायकोट में ग्राहकों को नशीली गोलियां सप्लाई कर रहा है। पुलिस ने तुरंत रेड कर आरोपी को 15 नशीली गोलियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। क्राइम रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत संबंधित थानों में मामले दर्ज कर लिए हैं। पुलिस द्वारा आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है ताकि नशे की सप्लाई चेन के मुख्य स्रोतों का पता लगाया जा सके।

लुधियाना में 16 वर्षीय छात्रा अगवा: स्कूल से छुट्टी के बाद नहीं लौटी तो परिजनों ने शुरु की खोजबीन, पुलिस खंगाल रही सीसीटीवी फुटेज

लुधियाना/ यूटर्न/20 मार्च। लुधियाना में एक 16 वर्षीय छात्रा के सदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है, जिससे इलाके में चिंता का माहौल बन गया है। परिजनों की



शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी

खंगाली जा रही है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि छात्रा स्वयं कहीं गई है या उसका अपहरण किया गया है। छात्रा की मां ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनकी बेटी, सोम्या (काल्पनिक नाम), 18 मार्च को रोज की तरह अपने प्राइवेट स्कूल गई थी। स्कूल की छुट्टी के बाद वह घर वापस नहीं लौटी। परिवार ने अपने स्तर पर उसकी काफी तलाश की, रिश्तेदारों और दोस्तों से संपर्क किया, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। परिवार ने आशंका जताई है कि उनकी बेटी को किसी अज्ञात व्यक्ति ने निजी स्वार्थ के चलते अपने कब्जे में लेकर कहीं छिपा रखा है। पुलिस ने इठर की धारा 127(6) के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लड़की की तलाश के लिए विशेष टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही उसे सुरक्षित बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है।

लुधियाना में गैंगस्टर्स की फिरौती कॉल्स से दहशत: बीते 4 दिनों में 4 कारोबारियों को मिली धमकी, 20 लाख से 5 करोड़ रुपए तक की मांग



लुधियाना/ यूटर्न/20 मार्च। पंजाब में गैंगस्टर्स के नाम पर धमकी और फिरौती मांगने के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिससे खासकर लुधियाना के कारोबारियों में दहशत का माहौल है। बीते चार दिनों में चार अलग-अलग व्यापारियों को धमकी भरे कॉल आने के बाद पुलिस भी हाई अलर्ट पर आ गई है। इनमें तीन बेकरी संचालक और एक ज्वेलर शामिल हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, इन कॉल्स में कुख्यात गैंगस्टर्स गोल्डी बराड़ और गोपी लाहोरिया के नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि, यह भी आशंका जताई जा रही है कि कुछ शातिर लोग इन नामों का गलत इस्तेमाल कर डर फैलाने और पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। एक मामले में पाल जी बेकरी से जुड़े गुरप्रीत सिंह को फोन कर खुद को गोपी लाहोरिया बताने वाले व्यक्ति ने 20 लाख रुपये की मांग की और पुरानी फायरिंग की घटना का हवाला देकर धमकी दी। वहीं सराफा बाजार के ज्वेलर तुषार भंडारी से कॉल कर खुद को गोल्डी बराड़ बताने वाले आरोपी ने 5 करोड़ रुपये की फिरौती मांगी और व्हाट्सएप पर हथियारों के इमोजी भेजकर डराने की कोशिश की। इसके अलावा अन्य बेकरी कारोबारियों को भी इसी तरह निशाना बनाया गया है। लगातार बढ़ते मामलों के बाद पुलिस कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी और व्यापारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी।

मोहाली पुलिस ने चोरी का मामला सुलझाया, 4 आरोपी गिरफ्तार

भूपिंदर सागर
मोहाली/यूटर्न/20 मार्च।
मोहाली पुलिस ने सेक्टर-77
स्थित एक कोठी में हुई चोरी के
मामले का खुलासा करते हुए चार
आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस ने इनके कब्जे से करीब
37 तोले सोने के गहने, 1.50
लाख रुपये नकद, एक .30 बोर
पिस्टल सहित दो जिंदा कारतूस
और अन्य सामान बरामद किया
है। पुलिस के अनुसार यह घटना
14 फरवरी को हुई थी, जब
शिकायतकर्ता प्रशांत वशिष्ठ
अपने रिश्तेदार के घर शादी
समारोह में शामिल होने आए थे।
रात के समय उनके कमरे से गहनों
और नकदी से भरी अटैची चोरी
हो गई थी। इस संबंध में थाना
सोहाना में 15 फरवरी को अज्ञात
आरोपियों के खिलाफ मामला
दर्ज किया गया था।
मामले की गंभीरता को देखते
हुए एसएसपी के निर्देश पर थाना
सोहाना और सीआईए स्टाफ की
संयुक्त टीम गठित की गई। पुलिस
ने तकनीकी और मानव स्रोतों की

सोने के गहने, नकदी और पिस्टल बरामद



मदद से जांच आगे बढ़ाई। इसी
दौरान 11 मार्च को हिमाचल
प्रदेश के मकलोडगंज से तीन
आरोपियों को गिरफ्तार किया
गया, जबकि एक अन्य आरोपी
को लुधियाना बस स्टैंड के पास
से काबू किया गया।

पूछताछ में चौकाने वाला
खुलासा हुआ कि आरोपी नेहा
धमीजा, जो पिछले चार-पांच
महीनों से शिकायतकर्ता के घर में
बेबी केयर का काम कर रही थी,
को घर में रखे गहनों और नकदी
की पूरी जानकारी थी। उसने अपने
साथियों के साथ मिलकर चोरी

की साजिश रची और वारदात को
अंजाम दिया।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान
बलकार सिंह उर्फ बांबी (21),
जसकरण सिंह उर्फ जस (26),
प्रीतपाल सिंह उर्फ अर्शी (19)
और नेहा धमीजा (26) के रूप
में हुई है। सभी आरोपी जिला मोगा
के बाधा पुराना क्षेत्र के रहने वाले
हैं। पुलिस के मुताबिक प्रितपाल
सिंह के खिलाफ पहले भी
एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला
दर्ज है। जांच में यह भी सामने
आया है कि चोरी की रकम से
आरोपियों ने मध्य प्रदेश से अवैध

पिस्टल और कारतूस खरीदे थे,
ताकि आगे और वारदातों को
अंजाम दिया जा सके। इसके
अलावा कुछ सामान आरोपियों ने
नीलों नहर में फेंक दिया था।

पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल
की गई स्विफ्ट डिजायर कार भी
बरामद कर ली है। फिलहाल सभी
आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं और
उनसे गहन पूछताछ की जा
रही है।

पुलिस को आशंका है कि इस
गिराह का संबंध अन्य चोरी की
घटनाओं से भी हो सकता है।
मामले की आगे की जांच जारी है।

चंडीगढ़ में बीच सड़क पर पत्थरबाजी: रोकने पर भी नहीं
रुके, जमकर लात-धूसे चले, VIDEO सामने आया



चंडीगढ़/यूटर्न/20 मार्च। चंडीगढ़ के सेक्टर-22 स्थित लाइट
पॉइंट पर बीच सड़क दो लोगों के बीच जमकर मारपीट और
पत्थरबाजी का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो भी
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता
है कि एक व्यक्ति ब्लैक जैकेट में है, जबकि दूसरा कुर्ता-
पायजामा पहने हुए है। शुरूआत में ब्लैक जैकेट पहने व्यक्ति ने
पत्थर उठाकर दूसरे पर फेंका। इसके जवाब में कुर्ता-पायजामा
पहने व्यक्ति ने भी बड़ा पत्थर उठाकर हमला किया, लेकिन सामने
वाला बाल-बाल बच गया। इसके बाद दोनों ने छोटे-छोटे पत्थरों
से एक-दूसरे पर वार करना शुरू कर दिया। मौके पर मौजूद लोगों
ने बीच-बचाव करने की कोशिश की, लेकिन दोनों नहीं माने और
फिर हाथापाई पर उतर आए। दोनों के बीच लात-धूसे भी चले।
फिलहाल झगड़े की वजह और दोनों व्यक्तियों की पहचान स्पष्ट
नहीं हो पाई है।

जीरकपुर एरोसिटी में गुटका साहिब की बेअदबी:
अंग इलाके में बिखरे मिले, सूचना मिलते ही
मौके पर पुलिस पहुंची, मामले की जांच शुरू



चंडीगढ़/यूटर्न/20 मार्च। जीरकपुर के एरोसिटी इलाके में
एयरपोर्ट रोड पर गुटका साहिब की बेअदबी का मामला सामने
आने से इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। सड़क के बीच
बनी एक समाधि के पास गुटका साहिब के अंग बिखरे मिलने के
बाद स्थानीय लोगों और सिख संगत में भारी आक्रोश देखा जा रहा
है। घटना एरोसिटी के एच ब्लॉक में उस समय सामने आई, जब
छत गांव के कुछ लोग शाम के समय सैर कर रहे थे। उन्होंने
समाधि के पास गुटका साहिब के बिखरे अंग देखे और तुरंत
पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची
और पूरे इलाके को सील कर दिया गया। पुलिस आसपास लगे
सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और संदिग्ध लोगों की
पहचान करने में जुटी है। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में
लोग और सिख संगत मौके पर इकट्ठा हो गई और दोषियों के
खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को
देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। प्रशासन ने
लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और आश्वासन दिया
है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।

चंडीगढ़ में डेंगू पीड़ित छात्रा की मौत में अस्पताल दोषी: मोहाली के निजी हॉस्पिटल व 3 डॉक्टरों पर 45 लाख जुर्माना, ICU में कैथेटर 32 घंटे गलत

चंडीगढ़/यूटर्न/20 मार्च। चंडीगढ़ राज्य
उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने मोहाली
स्थित Ivy Hospital और उसके तीन डॉक्टरों
को 19 वर्षीय छात्रा गुरप्रीत कौर की मौत के
मामले में गंभीर मेडिकल लापरवाही का दोषी
ठहराया है।

आयोग ने अस्पताल और संबंधित डॉक्टरों
पर कुल 45 लाख रुपये का मुआवजा लगाया,
जबकि सेक्टर-16 स्थित सरकारी अस्पताल
को इस मामले में क्लीन चिट दे दी गई। यह
मामला चंडीगढ़ निवासी कविता की बेटी
गुरप्रीत कौर से जुड़ा है, जो बीकॉम की छात्रा
थी और आईएस बनने का सपना देखती थी।
19 दिसंबर 2021 को उसे दस्त और अन्य



लक्षणों के चलते सरकारी अस्पताल में भर्ती
कराया गया था, लेकिन हालत बिगड़ने पर 20
दिसंबर को Ivy Hospital, मोहाली में शिफ्ट
किया गया। 22 दिसंबर 2021 को उसकी
मौत हो गई। आयोग ने पाया कि अस्पताल में

सेंट्रल वेनस कैथेटर गलत जगह लगाया गया,
जो करीब 32 घंटे तक पता नहीं चल पाया।
कठम प्रोटोकॉल के तहत इसकी तुरंत जांच
जरूरी थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसे
आयोग ने गंभीर लापरवाही माना। इसके
अलावा डेंगू टेस्ट में भी करीब 5 घंटे की देरी
हुई और रिपोर्ट समय पर नहीं आई, जिससे
इलाज प्रभावित हुआ। मामले में डॉ. गुरप्रीत
सिंह बबरा, डॉ. चेतन गोयल और डॉ. राजीव
धुनना पर भी जुर्माना लगाया गया है। आयोग
ने अस्पताल को 10 लाख और तीनों डॉक्टरों
को कुल 35 लाख रुपये मुआवजा देने का
आदेश दिया, साथ ही 40 हजार रुपये मुकदमे
की लागत भी निर्धारित की।

देश की भावी पीढ़ी को भगवान श्री परशुराम के पदचिन्हों पर चलने की प्रेरणा मिलेगी भव्य चौक से: डा. अरविंद शर्मा

चंडीगढ़/यूटर्न/20 मार्च। डा. अरविंद शर्मा
ने कहा कि पिहोवा में निर्मित भगवान
भगवान श्री परशुराम चौक आने वाली
पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि
यह चौक युवाओं को परशुराम के आदर्शों
पर चलने का आत्मबल देगा और तीर्थ नगरी
के सौंदर्यीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका
निभाएगा। नगरपालिका द्वारा आयोजित
कार्यक्रम में मंत्री ने चौक का उद्घाटन किया
और विकास कार्यों के लिए 11 लाख रुपये
की अनुदान राशि देने की घोषणा की। इस
दौरान उन्होंने मां सरस्वती मंदिर में पूजा-
अर्चना भी की। उन्होंने कहा कि पिहोवा



एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, जहां हर वर्ष
देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं।
यह भव्य चौक पर्यटकों को आकर्षित
करेगा और शहर की पहचान को नई दिशा
देगा। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब
सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य में पर्यटन को
बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य हो रहे
हैं। मोरनी हिल्स और कुरुक्षेत्र जैसे स्थानों
का तेजी से विकास किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी कहा कि सरस्वती नदी के
जल प्रवाह को पिहोवा तक लाने और
मुख्य मार्ग को फोरलेन बनाने की दिशा
में सरकार जल्द काम शुरू करेगी।

पंजाब में गऊ सैस पर बड़ा सवाल: 118 करोड़ का हिसाब गायब, 11 साल बाद भी नियम अधूरे

पंजाब/यूटर्न/20 मार्च। बेसहारा पशुओं की समस्या से निपटने के लिए लागू किए गए गऊ सैस को लेकर पंजाब सरकार एक बार फिर सवालों के घेरे में है। विधानसभा की सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी की रिपोर्ट में सामने आया है कि 2018 से 2021 के बीच एकत्रित करीब 118 करोड़ रुपये का स्पष्ट हिसाब उपलब्ध नहीं है।

11 साल बाद भी नियम अधूरे

साल 2014 में लागू पंजाब गौ सेवा कमीशन एक्ट, 2014 के तहत गऊ सैस लगाया गया था, लेकिन हैरानी की बात है कि 11 साल बीतने के बाद भी इसके नियम पूरी तरह अधिसूचित नहीं किए जा सके हैं। कमेटी ने सरकार को जल्द नियम नोटिफाई करने की सिफारिश की है।

फंड ट्रांसफर में लापरवाही

रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि विभिन्न विभागों द्वारा वसूला गया गऊ सैस डिप्टी कमिश्नरों तक सही तरीके से ट्रांसफर नहीं किया जा रहा। इससे फंड के उपयोग पर सवाल खड़े हो गए हैं।

ऑडिट नहीं, उपयोग पर संदेह

कमेटी ने पाया कि गऊ सैस फंड का महालेखाकार से ऑडिट तक नहीं कराया जा रहा, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा



कि पैसे का सही उपयोग हुआ या नहीं। कमेटी ने तत्काल ऑडिट कराने की सिफारिश की है।

मैरिज पैलेस और अन्य स्रोतों से कम वसूली

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मैरिज पैलेस और सीमेंट जैसे स्रोतों से अपेक्षित गऊ सैस नहीं मिल रहा। कमेटी ने सख्ती दिखाते हुए सुझाव दिया है कि सैस जमान करने वाले मैरिज पैलेस के लाइसेंस रद्द किए जाएं।

पीड़ितों को नहीं मिल रहा मुआवजा

बेसहारा पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में घायल लोगों को

मुआवजा नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया गया है, जबकि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मौजूद हैं।

जमीन पर नहीं दिख रहा असर, गऊ सेवा आयोग से जुड़े

अधिकारियों का कहना है कि सैस तो एकत्रित हो रहा है, लेकिन विभागों के बीच तालमेल की कमी के चलते इसका उपयोग पशुओं की देखभाल या उन्हें कैटल पाउंड में शिफ्ट करने में नहीं हो पा रहा। परिणामस्वरूप, सड़कों पर बेसहारा पशुओं की समस्या जस की तस बनी हुई है।

कमेटी की इस रिपोर्ट के बाद अब सरकार की कार्यप्रणाली और जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।

बटिंडा पुलिस ने ड्रग तस्करो के खिलाफ (CASO) सर्च ऑपरेशन चलाया

सोनु टुटेजा बटिंडा/यूटर्न/20 मार्च। पंजाब को ड्रग-फ्री राज्य बनाने के लिए शुरू किए गए 'वॉर ऑन ड्रग्स' के तहत, श्री गौरव यादव IPS DGP पंजाब के निर्देशों के अनुसार हर दिन पंजाब के अलग-अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज 19.03.2026 को बटिंडा सब-डिवीजन बटिंडा रूरल पुलिस स्टेशन सदर बटिंडा के बस्ती बीर तालाब के इलाके को बांटकर एक सरप्राइज (CASO) ऑपरेशन के तहत सर्च ऑपरेशन चलाया गया। यह सर्च ऑपरेशन श्री जतिंदर कुमार जैन, IPS माननीय DGP (PSPCL) डॉ. ज्योति यादव, IPS, सीनियर सुपरिटेण्डेंट ऑफ पुलिस बटिंडा के गाइडेंस में, श्रीमती हीना गुप्ता, PPS, SP (PBI) बटिंडा और श्री करमजीत सिंह, PPS DSP स्पेशल क्राइम बटिंडा और श्री हरविंदर सिंह सरां, अड बटिंडा रूरल की लीडरशिप में चलाया गया, जिसमें लगभग 355 पुलिस कर्मचारी तैनात थे। इस मौके पर बटिंडा पुलिस ने एक प्रेस नोट जारी कर



बताया कि जिले में बदमाशों और ड्रग्स के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीमों ने जिले के अलग-अलग इलाकों में कई संदिग्धों के घरों में अचानक सर्च ऑपरेशन चलाया।

इस सर्च ऑपरेशन से पहले, उस इलाके में आने-जाने वाले रास्तों को ब्लॉक और सील कर दिया गया था, ताकि कोई भी व्यक्ति अपने इलाके से बाहर न जा सके। यह सर्च ऑपरेशन जिले में 09 अलग-अलग जगहों पर एक साथ चलाया गया। इस सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने 76

घरों की चेकिंग की, 56 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पृच्छताछ की गई, 10 मामले दर्ज किए गए, कुल 56 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 55.52 ग्राम हेरोइन, 245 नशीली गोлияयां, 08 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गईं। बटिंडा पुलिस अपील करती है कि नशा रोकने के लिए पुलिस का सहयोग करें और पुलिस युवाओं को नशे के दलदल से निकालने के लिए गांवों/शहरों और कस्बों में नशे के खिलाफ जागरूकता सेमिनार लगाकर उन्हें खेलों से जोड़ने की कोशिश कर रही है।

हैबतपुर में पति-पत्नी से मारपीट, दर्जन से अधिक लोगों पर केस दर्ज

डेराबस्सी, यूटर्न, 20 मार्च। नजदीकी गांव हैबतपुर में पति-पत्नी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस संबंध में दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच कर रहे एएसआई अवतार सिंह के अनुसार, गांव हैबतपुर निवासी रविंदर सिंह पुत्र कृष्ण लाल ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि 18 मार्च की रात करीब 9:30 बजे उसकी पत्नी घर के बाड़े में थी, जबकि उसका भाई वहां मवेशियों को चारा डाल रहा था। इसी दौरान गांव के कुछ लोग अपने साथियों के साथ वहां पहुंचे और ललकारे मारने लगे। रविंदर सिंह के अनुसार जब वह गेट के पास पहुंचा तो आरोपियों ने उसे घेर लिया और उसकी बुरी तरह पिटाई की। आरोप है कि हमलावरों ने उसके भाई और पत्नी के साथ भी मारपीट की तथा उसकी पत्नी के कपड़े तक फाड़ दिए।

अमरनाथ यात्रा 2026: लंगर अनुमति प्रक्रिया पर गंभीर सवाल

चंडीगढ़/यूटर्न/20 मार्च। श्री अमरनाथ बफार्नी लंगर संगठन ने श्री अमरनाथ यात्रा 2026 के लिए लंगर संगठनों को अनुमति देने की नई प्रक्रिया पर गंभीर चिंता जताई है। संगठन का कहना है कि यह नई व्यवस्था पारदर्शिता और निष्पक्षता के मूल सिद्धांतों के विपरीत है और इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। संगठन के अध्यक्ष राजन गुप्ता ने बताया कि श्राइन बोर्ड द्वारा वर्षों से लागू अभिरुचि अभिव्यक्ति (ईओआई) आधारित पारदर्शी प्रणाली को बिना किसी स्पष्ट कारण के समाप्त कर दिया गया है। नई प्रक्रिया में न तो पात्रता के मानदंड घोषित किए गए हैं और न ही चयन के लिए कोई स्पष्ट मापदंड तय किए गए हैं, जिससे मनमानी और पक्षपात की आशंका बढ़ गई है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि वर्ष 2025 की यात्रा के बाद लंगर संगठनों को अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी नहीं किए गए, जबकि यह अगले वर्ष अनुमति प्राप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। इससे वर्षों से सेवा दे रहे संगठनों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। इसके अतिरिक्त, 25 मार्च 2026 को आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित होने के बावजूद अनुमति देने की कोई स्पष्ट समय-सीमा तय नहीं की गई है। संगठन का कहना है कि इससे तैयारियों, संसाधनों और वित्तीय योजना पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। SABLO ने मांग की है कि चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए, पूर्व प्रणाली को बहाल किया जाए और अनुभवी संगठनों को निष्पक्ष अवसर दिया जाए, ताकि तीर्थयात्रियों को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित की जा सकें।



चंडीगढ़ में पीसीआर कर्मियों पर वकील से बदसलूकी के आरोप, बार एसोसिएशन ने की कार्रवाई की मांग



अजीत झा चंडीगढ़/यूटर्न/20 मार्च। सेक्टर-44डी मार्केट में एक वकील के साथ कथित बदसलूकी और अभद्र व्यवहार के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जिला बार एसोसिएशन, चंडीगढ़ ने इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को शिकायत देकर संबंधित पीसीआर कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के अनुसार, 18 मार्च 2026 की रात करीब 11:30 बजे पीसीआर वाहन (नंबर CH01 GA 0725) में तैनात पुलिस कर्मियों ने अधिवक्ता उज्ज्वल भसीन के साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार किया। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने न केवल अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, बल्कि अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हुए उनके साथ अनुचित व्यवहार और संपत्ति को अवैध रूप से रोकने जैसी कार्रवाई भी की। उज्ज्वल भसीन, जो सेक्टर-44बी के निवासी हैं, जिला बार एसोसिएशन के सक्रिय सदस्य और वर्तमान में कार्यकारिणी के कोषाध्यक्ष भी हैं। इस घटना को लेकर पहले ही 19 मार्च को विस्तृत शिकायत पुलिस मुख्यालय को सौंपी जा चुकी है।



बार एसोसिएशन का कहना है कि इस तरह का व्यवहार न केवल एक अधिवक्ता की गरिमा के खिलाफ है, बल्कि पूरे कानूनी समुदाय का अपमान है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं पुलिस व्यवस्था में जनता के भरोसे को कमजोर करती हैं। एसोसिएशन ने मांग की है कि संबंधित पीसीआर कर्मियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करने की भी अपील की गई है।

हाई कोर्ट का बड़ा फैसला: सहकारी समितियों के 1997 सेवा नियम रद्द, रिटायर लाभों पर लगा ब्रेक

चंडीगढ़/यूटर्न/20 मार्च। पंजाब की सहकारी समितियों से जुड़े कर्मचारियों को बड़ा झटका देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने वर्ष 1997 के सेवा नियमों को अवैध घोषित कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन नियमों के आधार पर ग्रेजुएटी, लीव एनकैशमेंट और अन्य रिटायरमेंट लाभों का दावा नहीं किया जा सकता। यह अहम फैसला जस्टिस हरपीत सिंह बराड़ की पीठ ने कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए सुनाया। इनमें सेवानिवृत्त कर्मचारियों की याचिकाएं भी शामिल थीं, जिनमें बकाया लाभ और ब्याज की मांग की गई थी।

आर्थिक स्थिति पर भी टिप्पणी

कोर्ट ने माना कि अधिकांश सहकारी समितियां आर्थिक संकट से जूझ रही हैं और कई के पास कर्मचारियों का नियमित वेतन देने तक के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं। ऐसे में भारी-भरकम रिटायर लाभ देना संभव नहीं है।



नियमों को वैधानिक मान्यता नहीं

कोर्ट ने कहा कि 1997 के सेवा नियम न तो वैधानिक हैं और न ही इन्हें विधानसभा के समक्ष पेश किया गया। ऐसे में इन नियमों के आधार पर कोई कानूनी अधिकार उत्पन्न नहीं होता और न ही इन्हें लागू कराने के लिए अदालत का सहारा लिया जा सकता है।

याचिकाएं खारिज, समिति को राहत

अदालत ने कर्मचारियों की सभी याचिकाएं खारिज कर दीं, जबकि एक सहकारी समिति की याचिका को स्वीकार करते हुए अधिकारियों द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस रद्द कर दिया। साथ ही निर्देश दिया गया कि समिति को जबरन भुगतान के लिए बाध्य न किया जाए। हालांकि कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले से दिए गए रिटायरमेंट लाभों की कोई वसूली नहीं की जाएगी।

'सब-डेलीगेशन' को बताया अवैध

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि पंजाब कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 1961 के तहत सेवा नियम बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास है। 1963 के नियमों के जरिए यह शक्ति रजिस्ट्रार को सौंप दी गई थी, जिसके आधार पर 1997 के सेवा नियम बनाए गए। कोर्ट ने इसे 'सब-डेलीगेशन' करार देते हुए कानून के विरुद्ध बताया।

सहकारी समितियां स्वतंत्र संस्थाएं

फैसले में अदालत ने कहा कि सहकारी समितियां स्वतंत्र संस्थाएं हैं, जो अपने संसाधनों से कर्मचारियों का वेतन और अन्य खर्च उठाती हैं। राज्य सरकार इनकी वित्तीय जिम्मेदारी नहीं लेती, इसलिए इन पर सरकारी कर्मचारियों जैसे वेतन और रिटायरमेंट लाभ का बोझ डालना व्यावहारिक नहीं है।

ऑनलाइन निवेश के नाम पर 25 लाख की ठगी, चंडीगढ़ में साइबर जाल का शिकार हुआ कारोबारी



अजीत झा, चंडीगढ़/यूटर्न/20 मार्च। शहर में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर एक व्यक्ति से 25 लाख रुपये ठग लिए गए। इस घटना ने एक बार फिर साइबर अपराधियों के बढ़ते नेटवर्क और उनके नए-नए तरीकों को उजागर कर दिया है।

निवेश का लालच देकर फंसाया जाल में

पुलिस के अनुसार सेक्टर-8/ए निवासी अमित गुप्ता को अज्ञात ठगी ने ऑनलाइन निवेश का लालच दिया। शुरूआत में आरोपी ने भरोसा जीतने के लिए मुनाफे का झांसा दिया और फिर धीरे-धीरे बड़ी रकम निवेश करने के लिए प्रेरित किया। इसी प्रक्रिया में शिकायतकर्ता से करीब 25 लाख रुपये ठग लिए गए।

साइबर थाना सेक्टर-17 में केस दर्ज

मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर क्राइम थाना सेक्टर-17 में एफआईआर नंबर 44 दर्ज की गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 61(2) के तहत अज्ञात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

तकनीकी जांच के जरिए आरोपियों की तलाश

पुलिस अब डिजिटल ट्रेल, बैंक ट्रांजैक्शन और कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। शुरूआती जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि यह किसी संगठित साइबर गिरोह का काम हो सकता है, जो लोगों को निवेश के नाम पर निशाना बना रहा है।

शहर में बढ़ते साइबर फ्रॉड से चिंता

हाल के दिनों में चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में ऑनलाइन ठगी के मामलों में तेजी आई है। साइबर अपराधी सोशल मीडिया, फर्जी वेबसाइट और मोबाइल कॉल के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसा रहे हैं। इस घटना के बाद शहरवासियों में भी चिंता का माहौल है।

पुलिस की अपील सतर्क रहें

पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी ऑनलाइन निवेश योजना में पैसा लगाने से पहले उसकी पूरी जांच करें। अनजान लिंक, कॉल या मैसेज पर भरोसा न करें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना साइबर हेल्पलाइन या नजदीकी पुलिस स्टेशन को दें। पुलिस का दावा है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और पूरे गिरोह का खुलासा किया जाएगा।

पुलिस ने महिला सुरक्षा पर पांच दिवसीय वर्कशॉप आयोजित की

चंडीगढ़/यूटर्न/20 मार्च। महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस अधिकारियों की दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से चंडीगढ़ पुलिस द्वारा सेक्टर-26 स्थित रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में पांच दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। 'नारी सुरक्षा पर जांच अधिकारी' विषय पर आधारित यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 16 मार्च से



20 मार्च 2026 तक आयोजित किया गया। यह वर्कशॉप ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट (BPR&D) के मार्गदर्शन में एसपी/हेडक्वार्टर एंड ट्रेनिंग मनजीत के नेतृत्व और डीएसपी/ट्रेनिंग अमराव सिंह की निगरानी में संपन्न हुई। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को महिला सुरक्षा से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर जागरूक किया गया। इसमें साइबर क्राइम की जांच में ओपन-सोर्स टूल्स का उपयोग, सोशल मीडिया पर होने वाले अपराध, ऑनलाइन

दुरुपयोग, साइबर पोर्नोग्राफी, आपत्तिजनक कंटेंट को ब्लॉक और हटाने की प्रक्रिया जैसी जानकारियां दी गईं। इसके अलावा पोकसो 3 और जुवनाइल जस्टिस एक्ट का अवलोकन, फॉरेंसिक साइंस की भूमिका, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों की जांच, मानव तस्करी, और पीड़ितों के परीक्षण से संबंधित प्रक्रियाओं पर भी विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। प्रतिभागियों को संबंधित कानूनों में हुए नवीनतम संशोधनों, अधिकतम दोषसिद्धि

सुनिश्चित करने के लिए जांच प्रक्रिया, लापता महिलाओं और बच्चों के मामलों में मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs), तथा नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की भी जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में चंडीगढ़ पुलिस की महिला अधिकारी, जिनमें असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर और सब-इंस्पेक्टर रैंक की अधिकारी शामिल थीं, ने भाग लिया और इंटरैक्टिव सत्रों में सक्रिय रूप से सहभागिता की।

गुर्जर समाज को लेकर पंजाब में बड़ी हलचल, बच्चू सिंह बैसला 22 मार्च को पंजाब दौरे पर



चंडीगढ़, यूटर्न, 20 मार्च। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय संगठन मंत्री बच्चू सिंह बैसला 22 मार्च को अपने दो दिवसीय दौरे पर पंजाब पहुंचेंगे। इस दौरान उनके गुलाब चंद कटारिया से मुलाकात करने की संभावना जताई जा रही है। बैसला के हवाले से मिली

जानकारी के अनुसार, इस दौरे के दौरान प्रदेश कार्यकारिणी की अहम बैठक भी आयोजित होगी, जिसमें पंजाब में गुर्जर समाज के प्रतिनिधित्व को लेकर कोई बड़ा निर्णय या घोषणा की जा सकती है। गौरतलब है कि पंजाब में लगभग

9% आबादी रखने वाला गुर्जर समाज लंबे समय से राजनीतिक और प्रशासनिक भागीदारी बढ़ाने की मांग करता रहा है। ऐसे में यदि इस मुलाकात के दौरान कोई ठोस फैसला सामने आता है, तो इसका राज्य की राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए विभिन्न दलों द्वारा गुर्जर समाज को साधने के प्रयास तेज हो सकते हैं। यदि समुदाय से जुड़े किसी नए नेतृत्व को जिम्मेदारी सौंपी जाती है, तो यह आगामी चुनावी समीकरणों को

प्रभावित करने वाली अहम पहल साबित हो सकती है। हालांकि, इस संभावित मुलाकात की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, लेकिन बैसला ने अपने दौरे की पुष्टि कर दी है, जिससे राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

28 मार्च को शुरू होंगे 100 नए मोहल्ला क्लीनिक: सीएम बोले- मुख्यमंत्री सेहत योजना में सारा खर्च सरकार उठाएगी, विरोधियों को बोलने दो

पंजाब/ यूटर्न/20 मार्च। भगवंत मान ने बताया कि पंजाब सरकार ने होशियारपुर और कपूरथला मेडिकल कॉलेजों के टेंडर की प्रक्रिया पूरी कर ली है और जल्द ही इनका निर्माण कार्य शुरू होगा। मलेरकोटला में प्रस्तावित कम्युनिटी मेडिकल कॉलेज के लिए जमीन अधिग्रहण अंतिम चरण में है, जिसे ईद के मौके पर लोगों को समर्पित किया जाएगा। इसके अलावा 28 मार्च को 100 नए मोहल्ला क्लीनिक शुरू किए जाएंगे, जबकि 400 अन्य पर काम जारी है। चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की चार साल की रिपोर्ट पेश करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य में फिलहाल 883 आम आदमी क्लीनिक संचालित हैं और जल्द ही इनकी संख्या 1400 तक पहुंच जाएगी। उन्होंने दावा किया कि 94%



मरीज क्लीनिक सेवाओं से संतुष्ट हैं और ओपीडी आंकड़ा 5 करोड़ पार कर चुका है। सीएम ने बताया कि मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है। अब तक 25 लाख परिवार पंजीकृत हो चुके हैं और 1.60 लाख मरीजों का इलाज किया जा चुका है। सरकारी

अस्पतालों में दवाइयां मुफ्त दी जा रही हैं और कमी होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब ने अपनी आबादी के अनुसार बेहतर बजट प्रावधान किया है। साथ ही स्वास्थ्य क्षेत्र में रिकॉर्ड स्तर पर डॉक्टरों और स्टाफ की भर्ती भी की गई है।

बीसी विंग को मिला नया नेतृत्व, हरप्रीत तगड़ बने प्रधान

बटिंडा शहरी के हलका इंचार्ज बबली ढिल्लों सहित अन्य नेताओं ने नियुक्ति का किया स्वागत

सोनू टुटेजा
बटिंडा/यूटर्न/20 मार्च। आने वाले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए शिरोमणि अकाली दल ने संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। पार्टी की ओर से बटिंडा शहरी क्षेत्र में युवा नेता हरप्रीत सिंह तगड़ को बीसी विंग का प्रधान नियुक्त किया गया है। उनकी इस नियुक्ति से पार्टी कार्यकर्ताओं,



खासकर बीसी वर्ग में खुशी की लहर देखने को मिल रही है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, हरप्रीत सिंह तगड़ लंबे समय से संगठन

के साथ जुड़े हुए हैं और जमीनी स्तर पर सक्रिय भूमिका निभाते आ रहे हैं। उनकी नियुक्ति को संगठनात्मक मजबूती के रूप में देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इससे बीसी विंग को नया बल मिलेगा और पार्टी को आगामी चुनावों में फायदा होगा। नवनिर्वाचित प्रधान हरप्रीत सिंह तगड़ ने अपनी जिम्मेदारी के लिए पार्टी नेताओं का धन्यवाद किया।

यूपी में बड़ा सियासी फेरबदल तय, योगी कैबिनेट विस्तार से साधेंगे नए समीकरण

उत्तर प्रदेश / यूटर्न/20 मार्च। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बीच लगातार बैठकें हो रही हैं। सूत्रों के अनुसार, अगले सप्ताह मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना है, जिसमें क्षेत्रीय संतुलन, जातीय समीकरण और संगठनात्मक मजबूती पर ध्यान रखा जाएगा। इस विस्तार में कुल मंत्रियों की संख्या 60 तक पहुंच सकती है, जिसमें नए और अनुभवी नेताओं का मिश्रण होगा। चर्चा में प्रमुख नाम



हैं: चौधरी भूपेंद्र सिंह, जो पश्चिमी यूपी के जाट वोटर्स के लिए रणनीतिक हैं; अशोक कटारिया, अनुभवी संगठन और सरकार का संतुलन बनाने वाले; पूजा पाल, दलित-पिछड़े वर्ग में प्रभावशाली महिला नेता; बलदेव सिंह

औलख, तराई क्षेत्र और सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व; और गोविंद नारायण शुक्ला, ब्राह्मण वोटबैंक और संगठन-सरकार तालमेल के लिए। इस विस्तार से पश्चिमी यूपी, प्रयागराज और तराई में जातीय व सामाजिक समीकरण मजबूत होंगे। तीसरे उपमुख्यमंत्री के पद पर भी चर्चा है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह कदम बीजेपी की घर-घर रणनीति और संगठन-सरकार समन्वय का ट्रेलर है और 2027 चुनाव में पार्टी की पकड़ को और मजबूत करेगा।

अस्पताल में मौत के बाद हफ्ते से बाँडी को पोस्टमार्टम का इंतजार

डेराबस्सी/यूटर्न/20 मार्च। डेराबस्सी का नाम-पता लिखवाकर जीएमसीएच, चंडीगढ़ में दाखिल हुए एक व्यक्ति की मौत के हफ्ते बाद भी पुलिस के लिए उसके वारिसों को ढूंढना टेढ़ी खीर बना हुआ है। हफ्ते से करीब 50 वर्षीय मृतक की बाँडी अस्पताल की मॉर्चरी में पड़ी है परंतु शिनाख्त के अभाव में बाँडी का पोस्टमार्टम नहीं हो पा रहा। डेराबस्सी पुलिस के जांच अफसर एसआई दिलबाग सिंह ने बताया कि 9 मार्च को विनोद कुमार पुत्र सूरजलाल नामक एक व्यक्ति पेट में तकलीफ के चलते खुद ही जीएमसीएच में दाखिल हुआ था। उसने अपना पता डेराबस्सी, मोहाली लिखा था परंतु उसके साथ कोई तीमारदार नहीं था। 15 मार्च की सुबह उसका निधन हो गया। जीएमसीएच द्वारा सूचित करने पर उसकी बाँडी वहां डेराबस्सी सिविल अस्पताल की मॉर्चरी में जरूर शिफ्ट कर दी गई परंतु अभी तक उसके वारिस समेत किसी जानकार तक का कोई अता पता नहीं चल सका है। मजबूरन पुलिस को बिना शिनाख्त के ही कानूनी कार्रवाई पूरी करनी पड़ रही है।

कोर्ट में राहुल गांधी का नागरिकता विवाद, कांग्रेस का सियासी हंगामा



नई दिल्ली/ यूटर्न/20 मार्च। राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर विवाद राजनीतिक और कानूनी रूप से फिर गरमा गया है। मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है। केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता एसबी पाण्डेय के माध्यम से दस्तावेजों की गोपनीयता का हवाला देते हुए सुनवाई चेंबर में कराने की मांग की, जिसे न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने स्वीकार किया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी वाड्ढा ने इस मुद्दे को लेकर भाजपा पर हमला बोला, जबकि भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कानून सबके लिए समान है और गोपनीयता राष्ट्रीय हित में आवश्यक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुप्पी साधी, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने राहुल का समर्थन किया। कानूनी जानकारों ने चेंबर सुनवाई को सामान्य प्रक्रिया बताया, जबकि कुछ अधिवक्ताओं ने पारदर्शिता पर सवाल उठाए। मामले में राहुल गांधी के जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट रिकॉर्ड और ब्रिटिश नागरिकता के पुराने फॉर्म पेश किए गए, जिनकी प्रामाणिकता पर राहुल पक्ष ने सवाल उठाया। अगली सुनवाई छह अप्रैल को तय की गई है। यह मामला लोकसभा चुनावों से ठीक पहले होने के कारण राजनीतिक रूप से संवेदनशील बन गया है। कांग्रेस इसे न्यायिक और राजनीतिक साजिश मान रही है, जबकि केंद्र ने कहा कि सभी दावे कानून के अनुसार जांच के योग्य हैं।

Alia Bhatt



तख्त श्री दमदमा साहिब के लिए 1,120 करोड़ रुपये का रेल लिंक मंजूर

चंडीगढ़/यूटर्न/20 मार्च। मोगा ज़िले में बीजेपी की 'बदलाव रैली' में अमित शाह के चुनाव का बिगुल बजाने के छह दिन बाद, रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने आज बटिंडा रेलवे स्टेशन का दौरा किया और घोषणा की कि तलवंडी साबो तक रेल कनेक्टिविटी की परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। तलवंडी साबो में ही तख्त श्री दमदमा साहिब स्थित है। उन्होंने कहा कि 1,120 करोड़ रुपये की इस परियोजना पर काम तब शुरू होगा, जब मानसा और बटिंडा, दोनों जिलों का सिविल प्रशासन जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर देगा। तख्त श्री दमदमा साहिब सिख धर्म की पाँच आध्यात्मिक गद्दियों में से एक है और यहाँ अभी तक रेल कनेक्टिविटी नहीं है। तलवंडी साबो, जिसे 'गुरु की काशी' के नाम से भी जाना जाता है, में हर साल 13 अप्रैल को बैसाखी के मौके पर एक भव्य मेला लगता है।



पहले संगत को आती थी परेशानी

फिलहाल, रेल लिंक न होने के कारण, तख्त श्री दमदमा साहिब जाने वाले तीर्थयात्रियों को बटिंडा में ट्रेन से उतरना पड़ता है और फिर आगे जाने के लिए बस या टैक्सी लेनी पड़ती है। बिट्टू ने कहा, पहले, मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के कार्यकाल के दौरान, इस प्रोजेक्ट पर काम राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच शेयरिंग के आधार पर करने का फैसला किया गया था, लेकिन अब रेलवे 1,118.47 करोड़ रुपये का पूरा खर्च खुद उठाएगा। रामन मंडी और सद्वा सिंहवाला गाँव के बीच 47.160 किलोमीटर लंबे ट्रैक के लिए, बटिंडा (151.912 हेक्टेयर) और मानसा (40.508 हेक्टेयर) जिलों में 192.42 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जाएगी। किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि इस काम के लिए 336 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास भी तेज होगा

बिट्टू ने आगे कहा कि रेल कनेक्टिविटी से न केवल तीर्थयात्रियों को पवित्र स्थल तक पहुँचने में आसानी होगी, बल्कि इससे इस क्षेत्र का सामाजिक-आर्थिक विकास भी तेज होगा। बेहतर परिवहन ढाँचे से पर्यटन को बढ़ावा मिलने और स्थानीय रोजगार के अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है। इसके अलावा, बिट्टू ने घोषणा की कि बटिंडा रेलवे स्टेशन का 100 करोड़ रुपये की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा, और इस संबंध में औपचारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी। गौरतलब है कि बटिंडा एशिया के सबसे बड़े रेलवे जंक्शनों में से एक है।

कई सालों से चल रही थी मांग

तलवंडी साबो तक रेल लिंक की माँग पिछले कई सालों से बार-बार उठाई जाती रही है। बिट्टू ने कई मुद्दों पर विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा, जिनमें तलवंडी साबो की रेल कनेक्टिविटी का लंबे समय से अटक हुआ काम भी शामिल था। उन्होंने कुछ अन्य रेलवे प्रोजेक्ट्स के बारे में भी बात की, जिनमें पटियाला-चंडीगढ़ और फि रोजपुर-अमृतसर लाइन शामिल हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, यह घोषणा आने वाले विधानसभा चुनावों के लिहाज से काफी अहम है; 14 फरवरी को शाह की रैली के बाद से ही बीजेपी ने राज्य में लोगों तक अपनी पहुँच बढ़ाने की कोशिशें तेज कर दी हैं।

32-34 किलोमीटर लंबे रेल लिंक बनाने की घोषणा

खास बात यह है कि 2013 के रेल बजट में, तब की संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे पवन कुमार बंसल ने तलवंडी साबो के रास्ते, मौर से रामा तक 32-34 किलोमीटर लंबे रेल लिंक बनाने की घोषणा की थी। जगह का सर्वे करने के बाद, अगस्त 2016 में राज्य सरकार को एक स्टेटस रिपोर्ट सौंपी गई थी। हालाँकि, किसानों के विरोध के चलते सर्वे का काम रोक दिया गया। इस रास्ते पर पड़ने वाले कई गाँवों के लोगों ने अपनी उपजाऊ जमीन के अधिग्रहण का विरोध किया, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट को टाल दिया गया।

राज्यसभा चुनाव: कांग्रेस ने क्रॉस-वोटिंग के लिए हरियाणा के 5वें विधायक को कारण बताओ नोटिस जारी किया

चंडीगढ़/यूटर्न/20 मार्च। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस-वोटिंग के मामले में पांचवें विधायक जरनैल सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कारण बताओ नोटिस शुक्रवार सुबह जारी किया गया। रतिया के विधायक से सात दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा के भीतर जवाब न देने पर कानून और पार्टी नियमों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा कांग्रेस की अनुशासन समिति के सदस्य-सचिव रोहित जैन ने बताया कि यह नोटिस समिति के अध्यक्ष धर्मपाल मलिक के निर्देश पर जारी किया गया है। इससे पहले, पार्टी ने चार अन्य विधायकों को भी इसी तरह के नोटिस जारी किए थे, जिनमें नारायणगढ़ के विधायक शैले



चौधरी, सढौरा (SC) की विधायक रेनु बाला, पुन्हाणा के विधायक मोहम्मद इलियास और हथीन के विधायक मोहम्मद इसराइल शामिल हैं।

समिति ने नोटिस में क्या कहा...समिति द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, रपार्टी नेतृत्व के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के

दौरान, आपने कथित तौर पर निर्धारित प्रक्रिया और पार्टी द्वारा जारी आधिकारिक निर्देशों के विपरीत मतदान किया, जिसके परिणामस्वरूप आपका वोट रद्द/अमान्य हो गया। यदि उपरोक्त कृत्य साबित हो जाता है, तो यह पार्टी के आधिकारिक रुख को विफल करने के उद्देश्य से किया गया एक जानबूझकर किया गया विचलन प्रतीत होता है, और यह पार्टी अनुशासन का गंभीर उल्लंघन है। ऐसा आचरण पार्टी विरोधी गतिविधियों के समान है और यह पार्टी की एकता, अखंडता और वैचारिक प्रतिबद्धताओं को कमजोर करता है। यह पार्टी के संविधान, नियमों और स्थापित मानदंडों का भी स्पष्ट उल्लंघन है।

भाजपा व कांग्रेस एक एक सीट जीती...हाल ही में हुए राज्यसभा चुनावों में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक-एक सीट जीती; हालाँकि, कांग्रेस के पाँच सदस्यों ने क्रॉस-वोटिंग की। इनमें से चार सदस्यों को बुधवार को ही कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया था, जबकि रतिया के विधायक जरनैल सिंह को यह नोटिस आज जारी किया गया है।

बलटाना में नगर परिषद का अतिक्रमण विरोधी अभियान, रेहड़ी-फड़ी हटाई गई



जीरकपुर, यूटर्न, 20 मार्च। शहर में बढ़ते अतिक्रमण पर लगाम लगाने के लिए नगर परिषद ने शुक्रवार को बलटाना क्षेत्र में बड़ा अभियान चलाया। पीर बाबा रोड मार्केट में इंफोर्समेंट टीम ने मौके पर पहुंचकर अवैध रूप से लगी रेहड़ी-फड़ी और अस्थायी स्टॉल्स को हटाया, जिससे लंबे समय से प्रभावित हो रही यातायात व्यवस्था को राहत मिली। कार्रवाई के दौरान सड़क किनारे किए गए अवैध कब्जों को हटाया गया और सार्वजनिक स्थानों को खाली कराया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य न केवल यातायात को सुचारू बनाना था, बल्कि पैदल राहगीरों को भी सुरक्षित रास्ता उपलब्ध कराना भी था।

अचानक हुई इस कार्रवाई से इलाके में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया। कई रेहड़ी-फड़ी संचालक जल्दबाजी में अपना सामान समेटते नजर आए, जबकि कुछ को टीम ने मौके पर ही हटाया। नगर परिषद की टीम ने सभी को स्पष्ट चेतावनी दी कि भविष्य में दोबारा अतिक्रमण करने पर जुर्माना और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इंफोर्समेंट विंग के इंस्पेक्टर अजय बराड़ ने कहा कि शहर में अवैध अतिक्रमण किसी भी सूत्र में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दुकानदारों और रेहड़ी-फड़ी संचालकों से अपील की कि वे सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कब्जा कर आम लोगों के लिए परेशानी न खड़ी करें।

उन्होंने आगे कहा कि नगर परिषद आने वाले दिनों में भी इसी तरह के अभियान लगातार चलाएगी, ताकि शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाया जा सके। स्थानीय लोगों ने भी इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि लंबे समय से सड़कें संकरी हो गई थीं और जाम की स्थिति बनी रहती थी। नगर परिषद की इस पहल से क्षेत्र में व्यवस्था सुधारने की उम्मीद जगी है।

14,000 रुपये रिश्वत लेते जेई गिरफ्तार, विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई

सोनु टुटेजा

चंडीगढ़, यूटर्न, 20 मार्च। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी कार्रवाई को जारी रखते हुए पीएसपीसीएल दफ्तर तलवंडी साबो,



जिला बटिंडा में तैनात जूनियर इंजीनियर लखवीर सिंह को 14,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एक स्थानीय निवासी की शिकायत के आधार पर की गई। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसके बेटे की गाड़ी गलती से बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे गाड़ी और खंभे दोनों क्षतिग्रस्त हो गए। मौके पर पहुंचे आरोपी कर्मचारियों ने कार्रवाई से बचाने के बदले 25,000 रुपये की मांग की, जो बाद में 15,000 रुपये पर तय हुई। शिकायतकर्ता ने पूरी बातचीत रिकॉर्ड कर ली और रिश्वत देने से इनकार करते हुए विजिलेंस से संपर्क किया। प्रारंभिक जांच के बाद टीम ने जाल बिछाकर आरोपी को सरकारी गवाहों की मौजूदगी में गिरफ्तार किया। सह-आरोपी की तलाश जारी है।